राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 308 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,14 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

ऑक्सीजन की कमी से गोवा में 15 की मौत

पणजी, (एजेंसी)। गोवा में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में संक्रमितों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को 15 मरीजों की कोविड से मौत हो गई। इसका कारण ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी बताई जा रही है। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ को यह जानकारी दी है। दो दिन पहले इस अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन के कारण 26 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवाई है। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने आशंका जताई है कि इनमें से कुछ मरीजों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने की वजह से हुई होगी।

अजित पवार का एकांउट राज्य सरकार संभालेगी

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया एकाउंट को मैनेज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार छह करोड़ रुपए खर्च करेगी। उनके पास वित्त मंत्रालय भी है। अजित पवार एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट से विधायक हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में बुधवार को निर्णय किया। सरकार की योजना अजित पवार की पहुंच आम आदमी तक बनाने की है। यही वजह है कि उनके द्वारा किये गये कार्यों और योजनाओं की जानकारी आम आदमी को दी जाएगी।

यूपीएससी परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी

नईदिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 स्थगित कर दी है और अब यह 10 अक्टूबर को होगी। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर 27 जून को निर्धारित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की गई है और अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। पिछले वर्ष भी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने के बाद चार अक्टूबर को कराई थी जबकि मुख्य परीक्षा जनवरी-2021 में हुई थी। पिछले वर्ष के उम्मीदवारों के इंटरव्यू एवं व्यक्तित्व परीक्षण अभी लंबित हैं। इंटरव्यू व सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद ही अगले वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।

शवों को गंगा में डालना गलतः एनएचआरसी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में तैरते शवों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। एनएचआरसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता को जागरूक करने और गंगा नदी में अधजली या बिना जली लाशों को बहाने से रोकने में असफल हुए हैं। शवों को हमारी गंगा में प्रवाहित करना स्पष्ट रूप से जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। गंगा नदी में बहते शवों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मौतों की जांच के लिए याचिका दाखिल की ।

'एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों के दो वक्त के खाने का करें इंतजाम,' दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खोलने का निर्देश दिया ताकि उन्हें और उनके परिवारों को दो वक्त का खाना मिल सके। कोरोना महामारी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने आज सुबह कहा था कि इनके लिए खाद्य सुरक्षा और सस्ते ट्रांसपोर्ट विकल्प को सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने गांव वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों से ट्रांसपोर्टर द्वारा अधिक पैसे वसूलने की समस्या का हल करने को भी कहा।

जस्टिस अशोक भूषण व एमआर शाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इनके लिए भोजन

व राशन का इंतजाम करने को कहा और अपने घर लौट रहे लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि वे आराम से घर जा सकें।

कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जताई और उनके लिए शुरू की गई योजनाओं पर राज्य सरकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल किया कि कोरोना महामारी के कारण बंद और लॉकडाउन ने इन्हें बेबस कर दिया है, इनके पास न रोजगार है और न पैसे। इनके पास खाने के लिए कमाई का कोई जरिया तो होना चाहिए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजदूरों और प्रवासियों के लिए राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारो को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली-हृष्टक्रमें बहु चर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोलें, ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूरों और प्रवासियों और उनके परिजनों को दो वक्त का खाना उपलब्ध हो सके. हृष्टक्रमें इन तीन राज्यों के जिले शामिल हैं, जहां की चर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन बनाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.

अगर कोई घर लौटना चाहे तो- लॉकडाउन और कर्फ्यू में काम-धंधे बंद पड़े हैं, ऐसे में जो प्रवासी दिल्ली-हृष्टक्र में रह रहे हैं उन्हें राशन मुहैया कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इन तीन राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या किसी अन्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए सूखा राशन उपलब्ध कराएं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से कहा है कि अगर दिल्ली-हृष्टक्र में फंसा कोई मजदूर अपने घर लौटना चाहता है तो सरकारें उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएं. याद हो कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर आय और खाने-पीने की कमी के चलते अपने-अपने गृह राज्य लौटने लगे थे.

स्पुतनिक वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होगी- स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस और टीकाकरण की स्थिति को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए नीति आयोग के सदस्य डा. वीके पॉल ने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीन की लगभग 18 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमेरिका में यह संख्या लगभग 26 करोड़ है। इस तरह भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आपूर्ति भी आगे बढ़ेगी। इसका उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और अनुमान है कि उस अवधि में 15.6 करोड़ खुराक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में स्पुतनिक 1 वैक्सीन आ गई है। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि वहां (रूस) से सीमित आपूर्ति की बिक्री अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 2 बिलियन डोज भारत में अगले पांच महीनों में उपलब्ध होगी। देसी और विदेशी वैक्सीन दोनों भारत में लगने लगेगी। स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में ही उत्पादित होकर मिलने लगेगी।

डॉ पॉल ने कहा कि एफडीए, डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित कोई भी टीका भारत आ सकता है। आयात लाइसेंस 1-2 दिनों के भीतर दिया जाएगा। कोई आयात लाइसेंस लंबित नहीं है। हम उन्हें अपनी कंपनियों के साथ यहां निर्माण के लिए आमंत्रित करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अच्छा काम किया। उन्होंने क्वाड के तहत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग, संबंधित अन्य विभाग और विदेश मंत्रालय शुरुआत से फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन के संपर्क में है। उनसे आधिकारिक तौर पर पूछा गया था कि क्या वे भारत में खुराक भेजना चाहते हैं या निर्माण करना चाहते हैं, हम भागीदार ढूंढेंगे और सहायता करेंगे।

उन्होंने कहा कि हर कंपनी के पास यह करने की क्षमता नहीं है। हम उन कंपनियों को खुला निमंत्रण देते हैं, जो ऐसा करना चाहती हैं। जो कंपनियां कोवैक्सिन का निर्माण करना चाहती हैं, उन्हें मिलकर करना चाहिए। सरकार सहायता करेगी ताकि क्षमता बढ़े। डॉ पॉल ने कहा है कि लोगों का कहना है कि कोवैक्सिन का निर्माण को अन्य कंपनियों को दिया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी, कोवैक्सिन निर्माण कंपनी (भारत बायोटेक) ने इसका स्वागत किया है। इस टीके के तहत जीवित वायरस निष्क्रिय हो जाता है और यह केवल बीएसएल 3 प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

डॉ. हर्षवर्धन ने की कोविड की स्थिति को लेकर कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गुरुवार को कोविड की स्थिति पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। हम 27 अप्रैल से गिरावट का रुख देख रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य में प्रतिदिन लगभग 50,000 नए मामलों की रिपोर्ट कर रहा है। 8 मई से राजस्थान सक्रिय मामलों में वृद्धि दिखा रहा है। दैनिक मौतों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। केरल के सभी जिलों में 15 अप्रैल से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दैनिक नई मौतों में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 से कर्नाटक में रोज नए मामलों में तेजी दिखाई दे रही है, बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित है। टीकाकरण में पीछे छूट रहे आठ राज्यों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि मई में देश में कुल आठ करोड़ टीके उपलब्ध हो पाएंगे, जो जून में बढ़कर नौ करोड़ हो जाएंगे। इनमें 50 फीसद केंद्र को और 50 फीसद राज्य सरकारों व निजी क्षेत्र को सप्लाई किए जाएंगे।

वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए हर्षवर्धन ने राज्यों को केंद्र से मिलने वाली 70 फीसद वैक्सीन दूसरी डोज में इस्तेमाल करने की सलाह दी। उनका कहना था कि प्राथमिकता समूह वाले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर अत्यधिक खतरे और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों में अत्याधिक मृत्युदर को देखते हुए यह करना जरूरी है। बैठक में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब,ओडिशा और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल थे।

नहीं होगी कोरोना के देसी टीके की कमी, अब दूसरी कंपनियों से भी कोवैक्सीन बनवाएगी सरकार

नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस के देसी टीके कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार दूसरी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार हो गई है। गुरुवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार अन्य कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टीके के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

पॉल ने कहा कि लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अन्य कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने इस संबंध में कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के साथ इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने इसका स्वागत किया है। बता दें फिलहाल भारत में तीन टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पूतकि वी शामिल है।

डॉ पॉल ने कहा कि हम उन कंपनियों को खुला निमंत्रण देते हैं जो कोवैक्सीन का मिलकर प्रोडक्शन करना चाहती हैं। पॉल ने आगे कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों की सहायता करेगी ताकि टीके के प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ सके। टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि फिलहाल 45 साल या उससे अधिक उम्र की एक तिहाई आबादी कवर हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई रायों ने केंद्र के सामने टीकों की कमी का मुद्दा उठाया था। टीके की कमी के बाद कई रायों में वैक्सीनेशन सेंटर को बंद भी करना पड़ा है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने कहा, भारत और देश के लोगों के लिए देश में पांच महीनों में दो अरब खुराक (216 करोड़) बनाई जाएंगी। टीका सभी के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल की प्रथम तिमाही तक यह संख्या तीन अरब होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़ खुराक का उत्पादन अनुमानित है, जबकि कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी।

कोविशील्ड के दो डोज के बीच का समय बढ़ा- भारत सरकार ने गुरुवार को कोविशील्ड टीके की दो डोज लगवाने के बीच के समय को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह करने की कोविड-19 कार्य समूह की सफारिश को स्वीकार कर लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविशील्ड के दो डोज के बीच समयांतर फिलहाल 6 से 8 सप्ताह का है।

100 जिलों के डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन 100 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा केस हैं। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को दो चरणों में जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

देश के नौ राज्यों में पड़ने वाले 46 जिलों के डीएम से पीएम मोदी पहली बैठक में बात करेंगे। इसके बाद अगले राउंड में 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे। यही नहीं इस मीटिंग के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से निपटने के उपायों, टीकाकरण और सख्ती जैसे मामलों पर बात कर सकते हैं। कोरोना संकट के बाद से पहला मौका है, जब पीएम नरेंद्र मोदी जिलाधिकारियों से बात करेंगे। अब तक पीएम मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, इस मीटिंग में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के जिलाधिकारी शामिल होंगे।

ममता बनर्जी फिर नाराजः सूत्र बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही इस कवायद से खासे नाराज हैं। वो मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी प्रकट कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी यह मानती हैं कि पीएम की सीधे डीएम के साथ मीटिंग करना सीएम को नजरअंदाज करने जैसा है जो देश के संघीय ढांचे का अपमान है।

दक्षिण-पूर्व अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अरब सागर में उठा तौकते तूफान आगे बढ़ रहा है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। शुक्रवार को यह लक्षद्वीप में छा जाएगा और धीरे-धीरे तेज होकर 16 मई तक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। मौसम विभाग के अनुसार तौकते तूफान के मजबूत होकर तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है।

इसके सुपर चक्रवात अम्फान की तरह और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक इसका असर हो सकता है।

हिंसा पीड़ितों से मिलने कूचबिहार पहुंचे गवर्नर

कूचबिहार ■ एजेंसी

प. बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कूच बिहार पहुंच गए हैं। जगदीप धनखड़ ने कूचबिहार पहुंचते ही कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं संविधान की रक्षा और उसे बनाए रखने और लागू कराने के लिए प्रयास करूं।

इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने भी 13 और 14 मई को बंगाल दौरे का ऐलान किया है। वह अपनी टीम अनुसूचित जाति आयोग से कहा था कि कोरोना के चलते फिलहाल दौरे को टाल दें। लेकिन विजय सांपला ने सरकार के अनुरोध के बाद भी दो दिन के दौरे की बात कही है।

धनखड़ बोले, संविधान बचाना मेरा कर्तव्य

2 मई को आए चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। कूचबिहार के अलावा जगदीप धनखड़ असम भी जाने वाले हैं, जहां हिंसा से बचकर कुछ लोगों ने शरण ले ली थी।

ईद की खरीदी हैदराबाद में गुरुवार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ढील के बीच ईद-उल-फितर के एक दिन पूर्व शाम को ऐतिहसिक चार मीनार के समीप भीड़ भरे बाजार का दृश्य।

कोविड से जुड़ा सामान चीन ने पांच गुना महंगा

बीजिंग, (एजेंसी)। भारत चीन में पिछले कुछ समय से मनमुटाव काफी बढ़ गया है। कोरोना से पूरे विश्व को जो क्षति हुई है उसके लिए चीन को ही दोषी ठहराया गया है जिसका बदला चीनी सरकार अब ले रहा है। चीन ने भारत में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाइयों के कांट्रेक्ट को रद्द कर दिया है ।

इसके साथ ही चीनी सप्लायर्स ने कोविड से जुड़े सामान की कीमतों में पांच गुना तक वृद्धि कर दी है। पिछले साल भी चीन ने महामारी के समय में वेंटिलेटर्स के दाम को बढ़ा दिया था। इतना ही नहीं चीनी सरकार ने भारत के सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते जरूरी सामान चीन से आयात नहीं हो पा रहे हैं।

सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर मंथन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर शिद्दत से विचार किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने गुरुवार को कहा कि वह शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में ठोस पहल करने से पहले वह कोर्ट के सभी जों की आम सहमति चाहेंगे।

जस्टिस रमना कोविड महामारी के मद्देनजर मीडियाकर्मियों की सुविधा के लिए मोबाइल एप लांच पर वीसी के जरिये मीडियाकर्मियों को सम्बोधित कर रहे थे। सीजेआई ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में शुरुआती दिनों में कुछ खामियां आ सकती हैं, पर इसे अनावश्यक रूप से तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने देश की न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को परम्परागत सिद्धांत करार देते हुए कहा कि इन प्रक्रियाओं तक आम लोगों की पहुंच महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का देश भर के लोगों की जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

आंध्र और तेलंगाना में टाला गया विधान परिषद चुनाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल सहित चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर आलोचना के बाद अब चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदों के लिए होने वाले द्विवार्षिकी चुनावों को टाल दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईसी ने इस मामले की समीक्षा की और निर्णय लिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराना तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और माहौल चुनावों के अनुकूल नहीं हो जाता।

कॉलर ट्यून पर चिढ़ा हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र के मोबाइल कॉलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जब भी कोई फोन लगाता है तो उसे चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए, कौन लगाएगा वैक्सीन, जब ये है ही नहीं। अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। अदालत ने कहा कि आपको सभी को वैक्सीन देनी चाहिए। अगर आप इसके लिए पैसे लेने जा रहे हैं तो भी इसे दीजिए। बच्चे भी कह रहे हैं. ये क्या है। ऐसे मामले में सरकार को थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक ही मैसेज बनाया और हमेशा उसी को चलाते रहें। जैसे एक टेप जब तक खराब नहीं हो जाता, तब तक बजता रहता है। आप भी इस मैसेज को 10 साल तक चलाएंगे।

केंद्र से पूछा- कॉल करने पर वैक्सीन लगवाने का मैसेज सुनाई देता है, जब वैक्सीन ही नहीं तो कैसे लगेगी?

राहत 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी आठवीं किस्त

किसानों के खाते में आज आएगा पैसा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वी किस्त डालेंगे। 9.5 करोड़ किसानों को 19 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने 7 मई तक लाभार्थी किसानों का एफटीओ जेनरेट कर दिया है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विट कर इस बात की जानकारी दी है कि 14 मई को सुबह 11 बजे पीएम किसान के लाभार्थी किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों में बहुत से ऐसे हैं, जिनकी किस्त नहीं आ रही है। इसकी वजह आपके आधार की फीडिंग, आधार कार्ड पर नाम और बैंक खाते के नाम में गडबडी. आधार ऑथंटिकेशन का फेल होना जैसे कई कारण हो सकते हैं। आप चाहें तो इन कारणों का घर बैठे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर पूरे गांव की लिस्ट भी देख सकते हैं।

जिससे पता चल जाएगा कि किन-किन लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। कौन कितनी किस्त ले चुका है और किसके खाते में क्या गड़बड़ी है। अगर आप को यह जानना है कि कितने किसानों का डेटा पहुंचा है तो डाटा रिसिव पर क्लिक करें, जिनका पेंडिंग है, वो दूसरे वाले बटन पर क्लिक कर स्थिति जान सकते हैं।

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

मुंबई, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।

पांच मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को निरस्त करते हुए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर पांच मई के फैसले पर पुनर्विचार करने की गहार लगाई है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिए गए आरक्षण की अधिकतम सीमा (50 फीसदी) का उल्लंघन है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। संविधान पीठ ने कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे में उन्हें आरक्षण के दायर में लाना सही नहीं है।

सार समाचार

पनामा के दक्षिण अपतटीय क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का नहीं कोई खतरा

पनामा सिटी। पनामा के दक्षिण अपतटीय क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 6.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय समयानुसार सुबह लगभग 9:42 बजे आया जो उत्तरी प्रशांत महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था› भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है तथा अन्य ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका।

प्रिंस फिलिप की याद ब्रिटेन की डाक सेवा जारी करेगी टिकट, बिक्री 24 जून से होगी शुरू

लंदन। ब्रिटेन की डाक सेवा 'रॉयल मेल' प्रिंस फिलिप की याद में विशेष टिकट जारी करेगी। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग एवं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति फिलिप का पिछले महीने 99 साल की उम्र में निधन हो गया था। रॉयल मेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिमोन थांप्सन ने कहा कि विशेष डाक टिकटों के जरिए फिलिप के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा, ''सात दशकों से अधिक समय तक वह (फिलिप) हमारे राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में रहे। उनका निधन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और हम उनकी याद में टिकट जारी करेंगे।'' इन टिकटों की बिक्री आधिकारिक रूप से 24 जून से शुरू होगी। प्रिंस फिलिप का गत नौ अप्रैल को विंडसर कैसल में निधन हो गया था।

धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर साधा निशाना

वाशिंगटन। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी विदेश नीति में प्राथमिक ध्यान मानवाधिकारों की बहाली पर देने के लक्ष्य पर आगे बढ़ने के क्रम में धार्मिक स्वतंत्रता के दमन के लिए चीन और कई अन्य देशों पर बुधवार को निशाना साधा। यह निंदा उसी तरह की है जो ट्रंप प्रशासन ने भी की थी जिसकी आलोचना अन्य अधिकारों से ज्यादा तवज्जो धार्मिक स्वतंत्रता को देने के लिए की जाती थी। यह कदम अमेरिकी स्थिति की फिर से पुष्टि करता है कि मुस्लिमों पर और पश्चिमी शिनजियांग में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर चीन की कार्रवाई 'नरसंहार' के दायरे में आती है। हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासन के व्यापक मानवाधिकार रणनीति का महज एक तत्व है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने मंत्रालय की वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट का हवाला देकर चीन की अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपासना करने की अनुमति न देने के लिए निंदा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व वरिष्ठ चीनी अधिकारी पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है जिन पर अमेरिका ने फालुन गोंग धार्मिक पंथ के सदस्यों का दमन करने का आरोप लगाया है।

अमेरिका के लास-वेगास में मिला कोरोना का भारतीय वैरिएंट, अधिकारियों ने की पुष्टि

लास वेगास (अमेरिका)। लास वेगास इलाका नेवाडा के उन स्थानों में शामिल हो गया है जहां अधिकारियों को कोरोना वायरस के उस स्वरूप के मामलों का पता चला है जो पहली बार भारत में मिला था। दक्षिणी नेवाडा स्वास्थ्य जिले की ओर से मंगलवार को बताया कि एक युवती जिसका हाल का यात्रा इतिहास नहीं है और उसे टीका नहीं लगा हुआ है, उसमें वायरस के उप प्रकार की पुष्टि हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिला प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि फिलहाल कोई अतिरिक्त मामले नहीं मिले हैं। वायरस के इस प्रकार के आठ अन्य मामले पहले उत्तरी नेवाडा में मिले थे जिनमें से चार मामलों की पुष्टि रेनो इलाके में पिछले हफ्ते हुई थी।

भारत में मौजूद कोरोना वायरस के बी1617 स्वरूप के खिलाफ प्रभावी है अमेरिकी स्वीकृत टीके

वाशिंगटन। अमेरिका ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे जिन कोविड-19 रोधी टीकों को मंजूरी दी है, वे भारत में मौजूद कोरोना वायरस के बी1617 स्वरूप के खिलाफ प्रभावी हैं। भारत कोविड-19 के इस स्वरूप के कारण महामारी के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. फ्रांसिस कोलिन्स ने कहा कि यह विश्लेषण कोविड-19 के स्वरूप और अमेरिका द्वारा स्वीकृत तीन प्रमुख टीकों के बारे में ताजा आंकड़ों पर आधारित है। कोलिन्स ने मीडिया से कहा, ''आंकड़ें आ रहे हैं और यह उत्साहजनक बात है कि अमेरिका द्वारा स्वीकृत टीके फाइजर, मॉडर्ना, जेएंडजे बी1617 नाम के इस स्वरूप के खिलाफ भी प्रभावी हैं।'' इस हफ्ते की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा था कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का बी1617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह 'स्वरूप चिंताजनक' है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि बी1617 में संक्रमण फैलाने की दर अधिक है।

इजराइल-गाजा हिंसा में 60 लोगों की मौत, भारत ने दोनों देशों हिंसा समाप्त करने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, 'भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है।' तिरुमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए।

अधिकारियों के मुताबिक, गाजा से फलस्तीनी चरमपंथियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले में इजराइल में 30 वर्षीय भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई। केरल के इदुक्की जिले की रहने वाली संतोष दक्षिण इजराइल के तटीय शहर एशकेलोन में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। भारत में इजराइल के राजदूत रोन माल्का ने भारतीय महिला की मौत पर ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। दोनों पक्षों की तरफ से जारी हमलों में अब तक 53 फलस्तीनी और छह इजराइली नागरिक मारे गए हैं। मंगलवार को भारत ने हरम अल शरीफ/ माउंट मंदिर में झड़पों एवं हिंसा तथा शेख जर्राह और सिलवान क्षेत्र में हो रहे निष्कासनों पर भी चिंता जतायी थी।

तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया था, 'भारत हरम अल शरीफ/ माउंट मंदिर में झड़पों एवं हिंसा पर बेहद चिंतित' है तथा 'शेख जर्राह और सिलवान क्षेत्र में हो रहे निष्कासनों पर भी उतना ही चिंतित हैं।' उन्होंने कहा था कि भारत दोनों पक्षों का आह्वान करता है कि वह जमीन पर यथास्थिति को बदलने से बचें। साथ ही कहा कि पुराने शहर में अल जवीया अल हिंदिया- भारतीय आश्रम भी है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का पालन करने की भी अपील की जो कहता है कि, 'पूर्वी यरूशलम समेत फलस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में इजराइल द्वारा 1967 से अन्य बस्तियों की स्थापना की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत घोर उल्लंघन है तथा दो राष्ट्र के समाधान को हासिल करने एवं स्थायी शांति में बड़ी बाधा है।'

तिरुमूर्ति ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्यक्ष शांति वार्ताओं को तत्काल फिर से शुरू करने और दो राष्ट्र समाधान को लेकर प्रतिबद्धता जताने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी 'कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र और इजराइल में गंभीर तनाव'' को लेकर अत्यंत चिंता व्यक्त की है जिसमें गाजा में पैदा हुआ हालिया तनाव भी शामिल है जो कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में हिंसा और तनाव को और बढ़ाता है।

इजराइल ने तेज किए गाजा में हवाई हमले, हमास के चीफ कमांजर्स को मार गिराया

गाजा सिटी। (एजेंसी)।

इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य हमला तेज कर दिया है जिसमें हमास के 10 शीर्ष चरमपंथियों की मौत हो गई और कई हवाई हमलों में वे इमारतें जमींदोज हो गईं जहां हमास के लोग रहते थे। इस्लामी उग्रवादी समूह ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है और उसने इजराइली शहरों में सैकड़ों रॉकेट दागे। महज तीन दिन में दोनों शत्रुओं के बीच लड़ाई ने 2014 के उस विध्वंसक युद्ध की याद दिला दी जो 50 दिन तक चला था। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी-अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजराइल ने सुबह होते ही कई हवाई हमले किए और गाजा में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया।

बुधवार को भी हवाई हमले जारी रहे थे जिससे हवा में धुएं का गुबार बन गया। गाजा सिटी में रात को सड़कों पर वीरानी छा गई और रमजान के आखिरी दिन लोग अपने घरों के भीतर ही सिमटे रहे। गाजा सिटी में अपनी इमारत में बम गिरने के बाद अन्य रिश्तेदारों के साथ भागकर मध्य गाजा में आए 44 वर्षीय जेयाद खत्ताब ने कहा, ''कहीं पर भी भाग नहीं सकते। कहीं पर भी छिप नहीं सकते।'' गाजा के उग्रवादी दिन भर इजराइल पर रॉकेट दागते रहे। गाजा के समीप दक्षिणी समुदायों में जनजीवन ठप हो गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 65 फलस्तीनियों की मौत हो गई है जिनमें 16 बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं। इस्लामी जिहाद ने सात चरमपंथियों की मौत की पुष्टि की है जबकि हमास ने एक शीर्ष कमांडर और कई अन्य सदस्यों के मारे जाने की बात कही है। इजराइल में कुल सात लोग मारे गए हैं जिनमें से चार की मौत बुधवार को हुई। इनमें टैंक रोधी मिसाइल से मारा गया एक सैनिक भी शामिल है और रॉकेट हमले में मारा गया छह साल का बच्चा भी शामिल है।

इजराइली सेना ने दावा किया कि हमास की बतायी संख्या से कहीं अधिक चरमपंथी मारे गए हैं। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र और मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष विराम के प्रयास चल रहे हैं लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं है। इजराइली टेलीविजन चैनल 12 ने बुधवार देर रात बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने हमला तेज करने के अधिकार दिये हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने गाजा में असैन्य इलाकों से इजराइली आबादी वाले इलाकों की ओर ''अंधाधुंध रॉकेट दागे'' जाने की निंदा की लेकिन साथ ही उन्होंने इजराइल से ''अधिक से अधिक संयम बरतने'' का भी अनुरोध किया।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने नेतन्याहू से इजराइल के अपनी रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करने का आह्वान किया और कहा कि वह तनाव खत्म करने की कोशिश के तहत एक वरिष्ठ राजनयिक को भेज रहे हैं। हिंसा का यह दौर एक महीने पहले यरुशलम में शुरू हुआ जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजराइली पुलिस तैनात रही और यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फलस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शनों को हवा दी और पुलिस के साथ झड़पें हुई। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। यरुशलम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने सोमवार देर रात इजराइल में कई रॉकेट दागे जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई।

इज़राइल और गाज़ा पट्टी की इस भीषण हिंसा में आम लोगों का सवाल, 'हम कहां जाएं?'

गाज़ा सिटी। (एजेंसी)।

गाज़ा सिटी में 50 वर्षीय उम्म माजिद अल रईस को अपनी और अपने चार बच्चों की इज़राइल के हवाई हमले से जान बचाने के लिए पड़ोस के घर में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि इज़राइल के जंगी जहाजों ने उनकी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। इज़राइल और गाज़ा पट्टी के बीच 2014 की जंग के बाद से सबसे भीषण हिंसा में इस हफ्ते हताहतों की संख्या बढ़ गई है जबकि अल रईस और अन्य फलस्तीनियों का सवाल है, 'हम कहां जाएं?' अल रईस ने पड़ोस के घर से फोन पर बताया, 'पूरा क्षेत्र एक छोटा सा हिस्सा है। यह एक जेल है। आप कहीं भी जाएं, आप निशाने पर हैं।' उन्होंने पड़ोस के घर में अपने किशोर बेटे-बेटियों के साथ शरण ली है। उन्होंने कहा कि बिना चेतावनी के इज़राइल ने हवाई हमले किए।

गाज़ा में 20 लाख लोग रहते हैं और यहां पर हवाई हमलों को लेकर सायरन या सुरक्षित घर नहीं हैं। बीते सालों में हुए टकरावों में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी आश्रय स्थलों तक पर हमला हुआ है। पिछले दो सालों में, इज़राइल ने हवाई हमलों के जरिए तीन बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया है जिनमें हमास के अहम दफ्तर थे। इज़राइल ने पहले चेतावनी के लिए गोलियां चलाईं ताकि इमारत में रहने वाले लोग भाग सकें। लड़ाकू विमानों ने बिना चेतावनी के कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इज़राइल का आरोप है कि इन इमारतों में चरमपंथी रहते हैं। कुल मिलाकर सोमवार से गाज़ा में 16 बच्चों समेत 65 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में चरमपंथी और आम नागरिक भी शामिल हैं। इनमें दो महिलाएं और बच्चे हैं जो इमारत पर हमले के दौरान मारे गए हैं।

एक महिला ने बताया कि इज़राइल के विमान ने बुधवार को एक दो मंजिला इमारत को निशाना बनाया जिसमें उनका चार वर्षीय पोता और गर्भवती बहू की मौत हो गई। उम्म मोहम्मद अल तलबानी ने अस्पताल में बताया, ÷ उन्होंने बिना चेतावनी के बम दाग दिए। घर में बच्चों के अलावा कोई न था।÷ इज़राइल की सरकार लंबे अरसे से आरोप लगाती रही है कि जवाबी हमलों के दौरान हमास आम नागरिकों को मानव कवच की तरह इस्तेमाल करता है और चरमपंथी अक्सर असैन्य इलाकों से रॉकेट दागते हैं और रिहायशी इमारतों में कमान केंद्र स्थापित करते हैं। फिर भी इज़राइल की हमास के साथ 2014 युद्ध में इमारतों को निशाना बनाने के लिए काफी आलोचना की गई थी। गाज़ा के निवासियों ने पहले की जंगों को याद करते हुए कहा कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वे इस संकरी क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। वर्ष 2007 में गाज़ा पर हमास के नियंत्रण के बाद से वह इज़राइल और मिस्र की नाकेबंदी का सामना कर रहा है। हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों ने तेल अवीव समेत इज़राइल के कई शहरों पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं जिनमें कम से कम सात लोगों की मौत हुई है।

इस साल भी फीकी रही ईद, कोरोना महामारी के कारण बंद रहे मस्जिदें

जकार्ता (इंडोनेशिया)। (एजेंसी)।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे वर्ष ईद-उल-फितर जोर शोर से नहीं मना सके। महामारी के कारण मस्जिदें बंद रहीं और इस उत्सव को मनाने के लिए परिवार के लोग एकजुट नहीं हो पाए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सड़कों पर लोग सामूहिक नमाज के लिए एकत्रित हुए, उन्होंने मास्क पहन रखे थे। कम जोखिम वाले इलाकों में मस्जिदों में नमाज की अनुमति दी गई लेकिन अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में मस्जिदें बंद रहीं। दक्षिणपूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जकार्ता स्थित इस्तिकला ग्रांड मस्जिद भी ईद पर बंद रही। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में ईद पर लगातार दूसरे साल लोगों को अपने संबंधियों के घर जाने के लिए यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने टेलीविजन पर संबोधन में कहा, ''ऐसे समय पर हमें अपने रिश्तेदारों की कमी खलती है, खासकर ईद के मौके पर। लेकिन अपने घरों को नहीं जाकर और एकजुट होकर हमें सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।'' पिछले वर्ष भी ईद के मौके पर इसी तरह की पाबंदियां थीं बावजूद इसके ईद की छुट्टी के तीन हफ्ते बाद इंडोनेशिया में संक्रमण के दैनिक मामले 37 फीसदी तक बढ़ गए थे। जकार्ता के गर्वनर ने मॉल, रेस्त्रां आदि को बंद करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बुडी गुनाडी सादिकीन ने चिंता जताई है कि यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद लोग आना जाना करेंगे और वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। दक्षिण फिलीपीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते और सरकारी बलों तथा मुस्लिम चरमपंथियों के बीच संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तौर पर नमाज अता करने की इजाजत नहीं दी गई है। मलेशिया में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने एकाएक ही एक और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी जो बुधवार से शुरू होकर सात जून तक चलेगा। अंतरराज्यीय यात्रा और सभी सामाजिक गतिविधियों पर भी रोक है।

भारत में कोविड-19 संकट को लेकर भारतीय-अमेरिकी सांसद ने की कमला हैरिस से मुलाकात

वाशिंगटन। कांग्रेस में सबसे लंबे समय से सदस्य रहे भारतीय-अमेरिकी अमी बेरा ने भारत में कोविड-19 संकट पर चर्चा करने के लिए यहां व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हैरिस के साथ कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस (सीएपीएसी) की 11 मई को हुई बैठक में भाग लेने के एक दिन बाद बेरा ने कहा, ''मैं भारत में चल रहे कोविड-19 संकट के बारे में उपराष्ट्रपति से सीधे बात करने का अवसर दिये जाने की सराहना करता हूं।'' उन्होंने कहा, ''बैठक में मैने भारतीय लोगों को निधि, तकनीकी विशेषज्ञता और टीके समेत तत्काल आवश्यक संसाधन भेजने के लिए बाइडन प्रशासन का आभार जताया।'' बेरा ने कहा कि वह भारतीय-अमेरिकी समुदाय द्वारा भारत में अपने परिवारों एवं मित्रों की सहायता करने के लिए संसाधन जुटाने में मदद में हैरिस के नेतृत्व की भी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और दुनियाभर में महामारी को रोकने के लिए मदद करने में अमेरिका एक सक्रिय वैश्विक नेता की भूमिका निभाता रहेगा। इस महामारी को खत्म करने और लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी नेतृत्व महत्वपूर्ण है।

भारत के बाद अब नेपाल में ऑक्सीजन की कमी, 16 कोविड मरीजों की मौत

काठमांडू। नेपाल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोविड-19 से संक्रमित 16 मरीजों की हाल में मौत हो गई। नेपाल में जानलेवा संक्रमण के 4,13,111 मामले आए हैं जबकि 4084 लोगों की मौत हुई है। 'हिमालयन टाइम्स' की खबर के मुताबिक, सरकार ने बुधवार को निजी अस्पतालों से कहा है कि वे ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 15 दिन में ऑक्सीजन संयंत्र लगवा लें। फैसले के मुताबिक, 100 बिस्तरों से अधिक की क्षमता वाले सभी अस्पतालों को अपने ऑक्सीजन संयंत्र लगवाने होंगे और सरकार इस बाबत जरूरी सहयोग देगी। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने कहा कि सभी अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करें। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ जोगेश्वर गौतम ने कहा, 卐 कई निजी अस्पतालों ने ऐसा नहीं किया है, हम कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संयंत्र स्थापित करने में उनकी मदद करेंगे।卐 सरकार ने अनुमान लगाया है कि ऑक्सीजन की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए करीब 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत है। इसके विपरीत, देश में केवल लगभग 8,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। महामारी से निपटने के लिए एक शीर्ष सरकारी निकाय कोविड -19 संकट प्रबंधन केंद्र ने बुधवार की बैठक में बताया गया कि जुलाई अंत तक देश को 50,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता हो सकती है। खबर के मुताबिक, बुधवार को काठमांडू घाटी के कुछ सरकारी अस्पतालों ने कहा कि उनके पास अब कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है लेकिनउनके पास ऑक्सीजन भरने के लिए पर्याप्त सिलेंडर हैं। 'माई रिपब्लिका' ने बुधवार को खबर दी है कि काठमांडू घाटी में कम से कम 12 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड-19 रोगियों को भर्ती नहीं करने की घोषणा की है।

ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बने

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका निभा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने बुधवार को कहा, ''ग्रिफिथ्स मुख्यालयों और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक एवं संचालन दोनों ही रूप में मानवीय मामलों में व्यापक नेतृत्व क्षमता का अनुभव लेकर आये हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान, वार्ता और मध्यस्थता का उन्हें खासा अनुभव है।''

ग्रिफिथ्स पिछले तीन साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं और छह साल से जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के हालिया प्रयासों के बारे में बुधवार को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अवगत कराया। गुतारेस ने कहा कि ग्रिफिथ्स यमन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत के तौर पर सेवा देते रहेंगे। ग्रिफिथ्स मार्क लोकॉक का स्थान लेंगे जिन्होंने चार साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वयक के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी और उनके काम की काफी सराहना भी हुई।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शीर्ष पदों के अनाधिकृत बंटवारे के तहत संयुक्त राष्ट्र में मानवीय एजेंसी का शीर्ष पद पारंपरिक रूप से किसी ब्रिटिश व्यक्ति को दिया जाता है। हालांकि इस चलन को खत्म करने की मांग उठ रही है और संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा अन्य देशों को देने की बात कही जा रही है लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पायी है।

अमेरिका के 57 सांसदों ने भारत को कोविड-19 संबंधी और सहायता देने का बाइडन से अनुरोध किया

वाशिंगटन। अमेरिका के 57 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडन को पत्र लिखकर भारत को दी जाने वाली कोविड-19 सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है। बाइडन को बुधवार को भेजे पत्र में सांसदों ने लिखा है, ''संक्रमण के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर भार बहुत अधिक बढ़ गया है। वायरस को खत्म करने के लिए हमें अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए।'' कांग्रेशनल इंडिया कॉकस में अध्यक्ष ब्रेड शेरमन ने कहा, ''भारत में कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर को लेकर हमें बहुत अधिक चिंता है। भारत वैश्विक महामारी कोविड-19 का केंद्र बन गया है। आज का दिन भारत के लिए बहुत कष्टदायी रहा है, वहां 4,205 लोगों की मौत हो गई और इन्हें मिलाकर अब तक 2,50,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं।'' पत्र में शेरमन ने कहा, ''भारत में कोविड-19 का हालिया प्रकोप एक मानवीय संकट है जिसमें हमें सहायता देने की जरूरत है। जब तक भारत में कोविड कहर बरपाता रहेगा तब तक वायरस के नए स्वरूपों की उत्पत्ति का जोखिम भी बना रहेगा जो टीकाकरण करवा चुके अमेरिकी लोगों के लिए भी एक गंभीर खतरा हो सकता है।'' उन्होंने कहा कि भारत को अतिरिक्त चिकित्सा उपकरणों, आपूर्तियों और अन्य आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है।

दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग घटी

दिल्ली सरकार के मुताबिक अब 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर्याप्त

नई दिल्ली (आनंद राय)। दिल्ली में घटते कोरोना रोगियों के साथ ही अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई है। जहां दिल्ली सरकार पहले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की मांग कर रही थी। वहीं अब दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के लिए 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर्याप्त है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली को यदि 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी मिले तो उससे दिल्ली का काम चल जाएगा।

राज्य सरकार के मुताबिक यदि दिल्ली को इससे ज्यादा की सप्लाई की जा रही है तो वह अतिरिक्त सप्लाई अन्य जरूरतमंद राज्यों को दे दी जाए ताकि वहां कोरोना रोगियों का उपचार किया जा सके। दिल्ली में कोरोना के नए मामले तेजी से कम हुए हैं। पहले कोरोना के नए मामले बढ़ने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ी थी। साथ थी ऑक्सीजन बेड की भी डिमांड थी। हालांकि अब ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड दोनों की मांग में कमी आई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में

पहले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की मांग कर रही थी दिल्ली सरकार

पहले दिल्ली के अस्पतालों में कम से कम 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। अदालत और केंद्र सरकार के सहयोग से 700 मीटर ऑक्सीजन एक ही दिन मिली। लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई थी। पिछले 48 घंटे से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पूरे सहयोग के लिए हम केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं। इस सहयोग के कारण दिल्ली में हजारों व्यक्तियों की जान बचाई जा सकी। दिल्ली में अब ऑक्सीजन की आवश्यकता 582 मीट्रिक टन प्रतिदिन रह गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा 'दिल्ली में लगभग 15 दिन पहले कोरोना के मामले बाढ़ की तरह बढ़ रहे थे। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 35 फीसदी तक पहुंच गया था। दिल्ली में प्रतिदिन 80 हजार से लेकर 1 लाख कोरोना टेस्ट रोज हो रहे थे। इन कोरोना टेस्ट में एक दिन में लगभग 28 हजार व्यक्ति तक पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अब इसमें गिरावट आई है। अगर आज गुरुवार की बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट 14 फीसदी आ चुका है।' वैक्सीन की कमी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा देश में वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या न हो लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज है। वैक्सीन की कमी पूरे देश में है।

अब पहले बिना रजिस्ट्रेशन करवाए वैक्सीनेशन केंद्रों पर लगवा सकते हैं टीका

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली के वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर एक रिव्यु मीटिंग की जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 45 प्लस आयुवर्ग के लोग अब बिना रजिस्ट्रेशन करवाए सीधे वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर टीका लगवा पाएंगे, वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही उनका रेजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि वैक्सीनेशन केंद्रों को अस्पतालों से शिफ्ट कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खोला जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 से 45 आयुवर्ग के लोगों के लिए 3 मई से वैक्सीनेशन केंद्रों की शुरुआत की गई थी। इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 45+ आयुवर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।

'गरीबों के आरक्षित बिस्तरों पर नहीं हो रहा मुफ्त इलाज'

निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करें केजरीवाल सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर निजी हस्पतालो में गरीब मरीजों के लिए आरक्षित मुफ्त बिस्तरों पर निशुल्क इलाज नही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों को सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध कराई है, दिल्ली के अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कई बार दिया है। वही केजरीवाल जो आम आदमी की पार्टी चलाने का दावा करते थे लेकिन इनकी सरकार ने कोरोना महामारी के काल में गरीबों से लूट का कार्य किया। चौथे लहर के दौरान गरीबों के लिए आरक्षित बिस्तरों पर मोटे पैसे लेकर इलाज किया। चौधरी अनिल कुमार ने माँग करी कि केजरीवाल कोरोना संक्रमित गरीब ईडब्ल्यूएस मरीजों को लूट की गई राशि वापस करें। तुरंत प्रभाव से निजी अस्पतालों में 25 फीसदी सीटें गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित करें। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि सामान्य मरीजों के इलाज के लिए केजरीवाल ने पिछले वर्ष 20 जून को जो दर तय किया था, उसका अधिकांश अस्पताल पालन नहीं कर रहे। केजरीवाल ने पिछले वर्ष जारी आदेश जिसमें दरें कांग्रेस शाषित राज्यों द्वारा तय दरें से काफी अधिक तय हुई थी, उसे भी लागू करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सामान्य मरीजों से हो रही लूट पर नियंत्रण के लिए रेट चार्ट बनाया जाने का भी मांग की। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में केजरीवाल ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया।

संक्षिप्त खबर

राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के डॉक्टर की हालत हुई नाजुक

नई दिल्ली। कोविड-19 के मरीजों की जान बचाने में संक्रमित हो रहे डॉक्टर के लिए डॉक्टर व अन्य एक जुट हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डॉक्टर के बचाव के लिए अभियान तेज कर दिया है। बुधवार देर रात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के बाल रोग विभाग में तैनात डॉ. अमित गुप्ता के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में एम्स, सफदरजंग सहित अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने मदद की गुहार लगाई। डॉ. गुप्ता अभी मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। गंभीर इनका परिवार 22 अप्रैल से अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है और कहीं भी इन्हें मदद नहीं मिली। इन्हें सांस लेने में कठिनाई होने पर उन्हीं के अस्पताल में लाया गया लेकिन वहां बेड ही नहीं मिला। उनके साथियों ने अपने स्तर पर चिकित्सा सुविधा दी और बाद में उन्हें अग्रसेन अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही हैं और अभी उन्हें एकमो मशीन की जरूरत है। वहीं उनकी बहन ऐना का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और दिलली सरकार के साथ साथ किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भाई ने अस्पताल में कोरोना वार्ड में उपचार किया, लेकिन जब आफत उन पर आई तो एक भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा।

निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की याद में मनाया गया समर्पण दिवस

नई दिल्ली। निरंकारी मिशन के बाबा हरदेव सिंह की याद में समर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि बाबा हरदेव सिंह ने मानवीयता से युक्त होकर जीवन जीने का ढंग सिखाया। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा लेने हेतु वर्चुअल रूप में समर्पण दिवस समागम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सत्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने निरंकारी जगत को संबोधित करते हुए फरमाया कि जब हम बाबा जी की केवल मुस्कान को याद करते हैं तो कितनी ठंडक महसूस होती है। उन्होंने हमें सच्चा मनुष्य बनने की युक्ति सिखायी। हम सही मायने में मानव की भांति अपना जीवन जीयें क्योंकि ऐसा ही भक्ति भरा, प्रेम वाला और निरंकार प्रभु से जुड़कर जिया गया जीवन ही बाबा जी को प्रिय था। उनकी शिक्षाओं पर चलकर हम प्रतिदिन अपने जीवन में निखार लायें ताकि यह ज्ञान की ज्योति घर घर में पहुंचे, जो उनकी अभिलाषा थी। बाबा हरदेव सिंह जी ने 36 वर्षों तक मिशन की बागड़ोर सम्भाली। उनकी छत्रछाया में मिशन 17 देशों से चलकर विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के 60 राष्ट्रों तक पहुंचा, जिसमें राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर के समागम, युवा सम्मेलन, सत्संग कार्यक्रम, समाज सेवा उपक्रम, विभिन्न धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ तालमेल जैसे आयोजन सम्मिलित थे।

दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर हुई 14 फीसदी

पिछले 24 घंटों में आए 10400 नए मामले

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर के कम होने और अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होने पर दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे को कम करने की मांग करते हुए एक ज़िम्मेदार सरकार की शानदार भूमिका का उदाहरण दिया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि, दिल्ली में अप्रैल के चौथे और मई के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी थी। प्रतिदिन 80 हज़ार से एक लाख तक टेस्ट किए जाते थे और रोज़ 27-28 हज़ार नए कोरोना मामले सामने आते थे संक्रमण की दर 32 फीसदी तक पहुंच गई थी। लेकिन अब दिल्ली में मरीजों की संख्या घट रही है

संक्रमण दर अब 14 फीसद है और पिछले 24 घंटो में केवल 10400 मामले सामने आए है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी तब दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। लेकिन संक्रमण दर के कम होने और अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होने के बाद दिल्ली में अब ऑक्सीजन की मांग भी घट गई है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि तत्काल में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बेड ऑक्सीजन की कुल मांग के अनुसार अब दिल्ली को रोज 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुश्किल के समय में सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा मांग के अनुसार 700 टन नहीं लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई जिससे हजारों लोगों की जान बची।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री जैन

'मुनाफा कमा रही हैं दोनों वैक्सीन कंपनियां'

एजेंसी

सीरम संस्थान और भारत बायोटेक को 16-16 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है : सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन की बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीन बना रही दोनों कंपनियां सीरम संस्थान और भारत बायोटेक 16-16 हजार करोड़ रुपए मुनाफा कमा रही हैं। दोनों कंपनियों को मुनाफा कमाने का बहुत ज्यादा अवसर दिया जा रहा है। कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन दे रही है, जबकि राज्य को 300 और प्राइवेट को 400 रुपए में दे रही है। वहीं, कोवैक्सीन इससे भी महंगी कीमत में वैक्सीन दे रही है।

जब कंपनी को 150 रुपए में भी फायदा हो रहा है, तो सभी के लिए वैक्सीन की कीमत 150 रुपए ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र-एक टेंडर पॉलिसी बनाकर केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीद कर सभी राज्य को दे। अलग- अलग राज्य को ग्लोबल टेंडर करने से हमारे देश की बदनामी होगी। साथ ही, वैक्सीन बना रहीं दोनों कंपनियों से फार्मूला लेकर दूसरी कंपनियों को साझा किया जाए, ताकि यथा शीघ्र देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बैठक में तीसरा मुद्दा यह उठाया कि वैक्सीन बना रही दोनों कंपनियों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर दिया जा रहा है। कोविशील्ड, केंद्र सरकार को केवल 150 रुपए में वैक्सीन देता है। उनके चेयरमैन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें उसमें भी मुनाफा है। अगर हम मान लेते हैं कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में दी जा रही वैक्सीन में कंपनी को 10 रुपए का भी मुनाफा है, तो कोविशील्ड हर महीने 6 करोड़ वैक्सीन बनाती है। अगर आधी वैक्सीन भी केंद्र सरकार को देनी होती है, यानि कि 3 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी है, तो कंपनी का मुनाफा करीब 30 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने आगे कहा कि कोविशील्ड अब वही वैक्सीन जो केंद्र सरकार को 150 रुपए में देती है, उसे राज्य सरकारों को 300 रुपए में देते हैं। जबकि वैक्सीन की कीमत एक ही होनी चाहिए। कंपनी ने राज्य सरकार को जो 300 रुपए की वैक्सीन दी, उसमें से 160 रुपए का मुनाफा हुआ। इसके अलावा, कंपनी इसी वैक्सीन को प्राइवेट को 400 रुपए में देते हैं। अगर हम वैक्सीन बनाने का कुल लागत 140 रुपए भी मान लें, तो यहां कंपनी को 260 रुपए का फायदा हो रहा है। यानि कंपनी को एक महीने के उत्पादन पर 960 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। इसी तरह कंपनी को औसतन 160 करोड़ रुपए प्रति एक करोड़ वैक्सीन पर मुनाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने डॉ. हर्ष वर्धन से कहा है कि देश के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 100 करोड़ लोग हैं। इनके लिए करीब 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी लगे वैक्सीन : अनुराग कुंडू

नई दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन (टीका) लगाने की सलाह दी है। आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा कि वर्तमान ने सरकार ने वैक्सीनेशन (टीकाकरण) अभियान से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं शामिल किया है। क्योंकि उन पर वैक्सीन का क्या असर होगा, इसके पुख्ता प्रमाण नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रसूति और स्त्री रोग फेडरेशन ने हाल ही में कहा है कि प्रसूति और स्त्रीरोग विशेषज्ञ और महिलाओं के स्वास्थ्य का देखभाल करने वालों को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

आयोग ने पत्र में सचिव को सलाह दी है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न सिर्फ वैक्सीन लगनी चाहिए बल्कि उन्हें एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी के रूप में वर्गीकृत भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाना चाहिए और इस फोर्स को वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।

टास्क फोर्स का काम महिलाओं को वैक्सीन लगने के बाद उसको प्रभावों को भी निगरानी करनी होगा। वहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महिलाओं को वैक्सीन के दुष्प्रभावों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर वैक्सीन के दुष्प्रभावों को लेकर शिक्षित करना चाहिए।

सिर्फ केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों को न दें विदेशी सहायता : दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार केंद्र सरकार से कहा कि जब वे विदेशों से आने वाले दवाओं व चिकित्सा उपकरणों का आवंटन करते हैं तो यह सिर्फ केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों को ही नहीं जाने चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी को सहायता दी जा रही है, तो इसका वितरण दिल्ली सरकार को करने दें। पीठ ने कहा कि जब आप दिल्ली को देते हैं, तो आपको केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जा रहे संस्थानों और अस्पतालों से परे देखना चाहिए। सहायता वहां जाना चाहिए जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इसका सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है।पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि स्थिति को सुधारा नहीं गया, तो वह उचित आदेश पारित करने में संकोच नहीं करेगा।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दावा किया कि सहायता का वितरण लक्षित और न्यायसंगत था। शुरूआत में वितरण को केंद्रीकृत किया गया था, लेकिन अब यह राज्यों को भेजा जा रहा है और वे खुद तय करते हैं कि किन संस्थानों को सहायता देना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि कल तक दिल्ली को दी जा रही सहायता दिल्ली सरकार को नहीं दी जा रही थी। पीठ ने केंद्र से पूछा यह स्थिति कब बदली गई है।

कोरोना के 33 दिन में सबसे कम 10,489 नए मामले, संक्रमण दर हुई 14.24 फीसद

नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 17.03 फीसद से घटकर 14.24 फीसद पर आ गई है। इस वजह से 33 दिन बाद दिल्ली में बृहस्पतिवार को सबसे कम 10,489 नए मामले आए। इससे दिल्ली को राहत मिलती दिख रही है। इससे पहले 10 अप्रैल को 7897 मामले आए थे। हालांकि, अभी 10 हजार से अधिक नए मामले आने के कारण कोरोना का संकट टला नहीं है। पिछले 24 घंटे में 15,189 मरीज ठीक हुए हैं।

इससे सक्रिय मरीजों की संख्या कम हुई है और मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। लेकिन चिंताजनक है कि यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 308 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक 13 लाख 72 हजार 475 मामले आ चुके हैं। जिसमें से 12 लाख 74 हजार 140 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 92.83 फीसद हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 20,618 हो गई है। मौजूदा समय में 77,717 सक्रिय मरीज हैं।

अस्पतालों में कम हुए मरीज

कोरोना के मामले कम होने से अस्पतालों में मरीजों का दबाव भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। छह मई को अस्पतालों में 20,117 मरीज भर्ती थे। वहीं मौजूदा समय में अस्पतालों में 18,211 मरीज भर्ती हैं। इस लिहाज से अस्पतालों में 9.47 फीसद मरीज कम हुए हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर में 607 व कोविड हेल्थ सेंटर में 70 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा 48,340 होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं।

24 घंटे 73,675 सैंपल की जांच- दिल्ली में अब तक कुल एक करोड़ 81 लाख एक हजार 281 सैंपल की जांच हुई है। जिसमें से 73,675 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई। जिसमें से 14.24 फीसद सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। सबसे अधिक संक्रमण दर 22 अप्रैल को 36.24 फीसद थी। उस दिन 72,208 सैंपल की ही जांच हुई थी। इसके मुकाबले अधिक जांच होने के बावजूद संक्रमण दर में गिरावट हुई है।

नए मामले 63 फीसद तक हुए कम- दिल्ली में सबसे अधिक 20 अप्रैल को 28,395 मामले आए थे। यदि इस आधार पर तुलना करें तो कोरोना के नए मामले करीब 63 फीसद कम हुए हैं। डाक्टर कहते रहे हैं कि यदि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन लोग सख्ती से करते रहे तो अगले कुछ दिनों में संक्रमण दर 10 फीसद से नीचे आ सकती है।

कांग्रेस में बढ़ा सलाह देने का चलन, किसी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी तो कोई दे रहा सीएम केजरीवाल को सुझाव

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच कांग्रेसी नेताओं की सलाह आजकल खासी चर्चा में हैं। नीचे से ऊपर तक सभी नेता मानो किसी सलाहकार परिषद के सदस्य बन गए हों। सोनिया, राहुल और प्रियंका जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते नहीं थकते वहीं प्रदेश के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार को ज्ञान बांटते रहते हैं। कभी यह सलाह या ज्ञान स्वास्थ्य सेवाओं पर तो कभी आक्सीजन संकट, कभी वैक्सीनेशन और कभी गरीबों के लिए राशन व्यवस्था को लेकर आ जाता है। सामने वाला कोई तव्वजो दे या नहीं, लेकिन कांग्रेसी ज्ञान इतनी गंभीरता से देते हैं, मानो उसी के आधार पर सब कुछ तय होगा। कांग्रेस की इसी सलाह और ज्ञान पर आज सियासी गलियारों और आम जनता सभी में चर्चा जोर पकड़ रही हैं? कि अगर पार्टी नेता इतने ही समझदार हैं? तो कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हैं? और क्यों लगातार हाशिये पर जा रही हैं?

फिर बंधी उम्मीद- केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी द्वारा पांच राज्यों में पार्टी की हार पर गंभीरता जताने से दिल्ली के कांग्रेसियों को भी थोड़ी उम्मीद बंधी है। दरअसल, पुराने और समर्पित कांग्रेसी पार्टी की लगातार पतली होती हालत से दुखी हैं। इनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व कों अपनी खामियां दूर करने और संगठन में बदलाव के लिए सोचना चाहिए। लेकिन आमतौर पर होता यही रहा है कि पार्टी के युवराज हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाते हैं। इसीलिए परदे के पीछे समूह 23 के नेताओं की सूची भी लंबी होती जा रही है। ऐसे में सोनिया गांधी के गंभीर रूख से वरिष्ठों को फिर उम्मीद बंध रही है कि शायद अब कुछ ढर्रे पर आ पाए। दिल्ली में भी पार्टी की खस्ता हालत पर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है। चिंगारी भड़कने और उसकी आंच महसूस होते ही कई दिग्गज एकाएक सक्रिय भी हो गए हैं।

संकट में भी मदद न कर पाने की लाचारी- कोरोना महामारी के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी पिछले एक पखवाड़े से नियंत्रण कक्ष चल रहा है। टविटर और हेल्पलाइन नंबर के जरिये करीब 1500 लोग मदद के लिए संपर्क कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ज्यादातर की मदद नहीं कर पा रही है। दरअसल, जनाधार घटने से पार्टी के पास संसाधनों का भी अभाव हो गया है।

जिला स्तर पर भी कुछ पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं जबकि कुछ पल्ला झाड़ ले रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष के लोग समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। जहां से मदद की गुहार आती है वहां के जिलाध्यक्ष के पास अग्रसारित कर दी जाती है। आक्सीजन की मांग पर संभव होता है तो मुहैया करा दी जाती है और अस्पतालों में बेड के लिए कोशिश करके देख ली जाती है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि ज्यादा न सही, जितना संभव है, कर रहे हैं।

शक्तियां हुई कम, कैसे करें समस्या का समाधान!- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का कामकाज आजकल सियासी दांव पेच में भी उलझ रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार ने आयोग के पुनर्गठन में वह प्रविधान तो हटा दिया जिसमें पराली जलाने वाले किसानों को कड़ी सजा दी जा सकती थी। अब न उन्हें जेल भेजा जाएगा और न ही उन पर मोटा जुर्माना लगेगा। ऐसे में आयोग समझ नहीं पा रहा कि पराली की समस्या का समाधान निकाले तो निकाले कैसे। मानसून सिर पर है और इसके बाद देखते ही देखते सर्दियों की आहट शुरू हो जाएगी।

इसी के साथ पराली का धुआं फिर से दिल्ली एनसीआर का दम घोटने लगेगा। इस समस्या का सुलझाने का जिम्मा सरकार ने आयोग को दे तो दिया, लेकिन इससे पहले उसे नख दंत विहीन भी कर दिया। अब आयोग के सदस्य समस्या का तकनीकी समाधान खोज रहे हैं। लेकिन अगर तकनीक से ही समस्या हल हो पाती तो शायद सालों पहले ही हो चुकी होती।

वेतन न मिलने पर विरोध पर उतरे सफाई कर्मचारी, प्रदर्शन करते हुए कहा- काम बंद करने को मत कीजिए मजबूर

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में कर्मचारियों को वेतन न मिलने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को सफाई कर्मियों ने महापौर आवास और निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर, जल्द समाधान न हुआ तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। उत्तरी के साथ ही दक्षिणी निगम में भी वेतन की समस्या इस माह देखने को आ सकती है, क्योंकि उनके पास भी वर्तमान में वेतन के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। निगम के अधिकारी फंड जुटाने के प्रयास में लगे हुए हैं।

तीन माह से नहीं मिला है वेतन- महापौर आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर गागट ने कहा कि तीन माह से वेतन नहीं मिला है तो हालत यह है कि ड्यूटी पर जाने के लिए किराया भी कर्मचारियों के पास नहीं है। ऐसे में महामारी के दौर में कर्मचारी अपने परिवार का इलाज किस तरह से करा रहे हैं यह वह ही जानते हैं। ऐसे में हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए। वेतन न मिलने की स्थिति में हम लोग कामबंद हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते है कि दिल्ली में गंदगी फैले और बीमारी बढ़े लेकिन हम भी अपने परिवार को चलाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर है।

दाने-दाने को मोहताज हैं- सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव करण सिंह महरौलिया ने कहा कि कर्मचारी इस समय दाने-दाने को मोहताज हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वह महामारी से लड़े या वेतन के लिए प्रशासन से, क्योंकि कर्मचारी इस समय काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वेतन के साथ कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दें हैं जिन पर काम नहीं हो रहा है। मैं एक नहीं कई बार दिल्ली सरकार को पत्र लिख चुका हूं कि कर्मचारियों का वेतन देने के लिए हमें फंड उपलब्ध कराए।

संपादकीय

संक्रमण थमेगा, तभी कारोबार जमेगा

अब सरकार को भी लग गया है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई है, वह बहुत घातक साबित हो रही है और इसका अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की कंपनियों पर कुछ ज्यादा ही असर पड़ा है। ऑटोमोबाइल व अन्य कुछ क्षेत्रों में अनेक छोटी कंपनियों ने अपने काम बंद कर दिए हैं। असर सभी पर है, लेकिन असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा है और इसीलिए पलायन भी दिख रहा है। सबसे पहले तो जो पैकेज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिया है, इसको हमें सरकार का पैकेज नहीं मानना चाहिए। सरकार अलग है और आरबीआई अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के मोर्चे पर कोशिश कर रहा है कि असंगठित क्षेत्र को कारोबार जारी रखने के लिए पैसा मिले, जिससे असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति और न बिगड़े। जो छोटे कारोबारी होते हैं, उनके पास पूंजी बहुत कम होती है और वह जल्दी खत्म हो जाती है। जब ऐसी इकाइयों में काम बंद होता है, तब इनके लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंपनियों को फिर शुरू करना भी कठिन होता है। इसीलिए छोटे कारोबारियों को पैकेज दिया गया है कि वे बैंक से ऋण ले सकें, लेकिन इससे स्थिति नहीं सुधरेगी। अभी तो और भी इकाइयां बंद हो रही हैं। जब तक संक्रमण की स्थिति नहीं संभलेगी, तब तक ये इकाइयां खुल भी नहीं पाएंगी। यह पैकेज बंद हो रही इकाइयों को थामने की कोशिश है, लेकिन इससे अभी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। हमलोग लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, अभी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इस समय में आपूर्ति शृंखला फिर से टूट रही है, जबकि हमने अभी तक पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया है। चयनित लॉकडाउन हो रहा है, इससे आपूर्ति में भी समस्या आने लगी है। जगह-जगह उत्पादों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उत्पादकों को उत्पादन भी बंद करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की भूमिका अभी सीमित है, उसकी कोशिश है कि व्यवसाय अभी लॉकडाउन की वजह से नाकाम न हों। यहां राहत दो तरह से मिल सकती है, या तो अभी काम जारी रखने के लिए ऋण मिल जाए या बैंक अभी ऋण की वसूली न करें। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मांग तत्काल नहीं बनेगी और आपूर्ति में कोई विशेष सुधार नहीं आएगा।

तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? हम देखते हैं, जहां भी विदेशी सरकारों ने कड़ाई से लॉकडाउन लगाया, वहां स्थितियां तेजी से ठीक होने लगीं। जैसे चीन है, उसने शुरू में ही संभाल लिया और ब्रिटेन ने एक सप्ताह की देरी कर दी, तो लेने के देने पड़ गए। लॉकडाउन लगाने में जहां भी देरी होगी, वहां दूसरी लहर देर तक चल रही है और जहां भी जल्दी लॉकडाउन लगता है, दूसरी लहर भी जल्दी काबू में आ जाती है। संक्रमण को आपने थाम लिया, तो आप अर्थव्यवस्था को जल्दी उबार सकते हैं। इसलिए मार्च से मैं कह रहा हूं, लॉकडाउन कर देना चाहिए। जिससे संक्रमण के मामले बढ़े नहीं। मामले बढ़ते ही इसलिए हैं कि लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तब दो सप्ताह बाद मामले घटने लगते हैं। हमारे यहां फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई थी, तीन महीने होने जा रहे हैं। लॉकडाउन न लगाने का खामियाजा यह है कि हमारे यहां रिकॉर्ड संख्या में मामले निकल रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। चूंकि हमने अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया है, इसलिए मामले अभी भी बढ़ने की आशंका है। एक दिक्कत यह भी है कि आंकड़े पूरे आते नहीं हैं या उपलब्ध नहीं कराए जाते। आज चिकित्सा व्यवस्था को बहुत तेजी से सुधारने की जरूरत है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने एक पैकेज दिया है। मेडिकल ढांचा विकसित करने के लिए विशेष ऋण की जरूरत पड़ेगी, उसे इस विशेष पैकेज के जरिए मुहैया कराया जाएगा। मेरा मानना है, ऐसा चिकित्सा ढांचा विकसित करने में समय लगता है, इसलिए सेना को बुला लेना चाहिए। सेना के पास अस्पताल भी होते हैं और परिवहन के साधन भी। सेना अगर आ जाए, तो राहत मिल सकती है। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। अभी विदेश से काफी सहायता आ रही है, जैसे कोई दवा दे रहा है, तो कोई ऑक्सीजन टैंक दे रहा है। आ रही मदद को हमें बढ़ा देना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में आयात बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोशिशों का विस्तार करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो पैकेज घोषित किया है, वह अच्छा है, लेकिन तत्काल उससे फायदा नहीं होगा। सेना और आयात, दोनों से मदद लेनी पड़ेगी।

अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। संक्रमण गांव-गांव पहुंच गया है, जहां चिकित्सा ढांचा मजबूत नहीं है। जहां जांच भी आसानी से नहीं हो पा रही है। गांव-गांव तक चिकित्सा ढांचा विकसित करना भी अभी किसी आफत से कम नहीं है। अभी संक्रमण को तत्काल रोकने की जरूरत है। ऐसे में, टीकाकरण भी काम नहीं आएगा। अभी तक नौ प्रतिशत लोगों को ही एक खुराक नसीब हुई है। हम वैक्सीन भी कम उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पूरी सामग्री भी नहीं है। हम अभी हर महीने पंद्रह करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं हैं। यह साल खतरे से खाली नहीं है। अब सरकार को आगे आकर इसमें जहां-जहां काम रुक गया, बेरोजगारी बढ़ी है, वहां-वहां मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों को इस वक्त मदद की बहुत जरूरत है। मुफ्त अनाज, इलाज जरूरी है। गरीब लोग पिछले साल बड़ी मुसीबत में चले गए थे। उस तरह का संकट अगर फिर आया, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी लोग संक्रमण से ही परेशान हैं और जब खाने-पीने का अभाव होगा, तो लोगों की परेशानी बहुत बढ़ सकती है। विशेषज्ञ बता रहे हैं, करीब 70-80 लाख लोगों ने रोजगार गंवाया है, पर मेरा मानना है कि इससे दस गुना ज्यादा लोगों ने काम गंवाया है। गांवों से जो खबरें आ रही हैं, वे भयावह हैं। इसका असर कृषि पर भी पड़ेगा। सरकार को गांवों तक मदद पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। लोगों की हताशा-निराशा को दूर करने के लिए सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे। आरबीआई के कदम कुछ दूर तक कारगर होंगे, लेकिन बाकी सब सरकार को ही करना पड़ेगा।

प्रवीण कुमार सिंह

पेटेंट कानून के कारण वैक्सीन महंगी है, अन्य कंपनियां कोरोना टीके को नहीं बना सकती

सर्वप्रथम सरकार को अपनी फार्मा कंपनियों को नए टीके विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे भविष्य में पैदा होने वाले वायरस के नए प्रतिरूपों का सामना करने के लिए हमारे पास टीकों की पर्याप्त शृंखला उपलब्ध हो। दूसरे सरकार को भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के पेटेंट को खरीद कर उसके फार्मूले को भारत की कंपनियों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को उपलब्ध करा देना चाहिए जिससे कोवैक्सीन का उत्पादन सारे विश्व में हो और हम बड़ी कंपनियों की मुनाफाखोरी को मात दे सकें। तीसरे, हमें डब्ल्यूटीओ को उत्पाद पेटेंट को लागू करने का प्रस्ताव देना चाहिए और डब्ल्यूटीओ न माने तो मुनाफाखोरी की संरक्षक इस संस्था से बाहर आ जाना चाहिए।

देश कोरोना संक्रमण के जिस कहर से जूझ रहा है, उसमें उम्मीद की एक बड़ी किरण यही है कि हमारे पास कोरोना रोधी टीके उपलब्ध हैं। वैसे तो सरकार ने अब कई विदेशी टीकों को भी हरी झंडी दिखा दी है, इसके बावजूद भारतीय टीकाकरण अभियान का दारोमदार मुख्य रूप से दो वैक्सीनों-सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर है। इन टीकों का अपना एक अर्थशास्त्र भी है। सीरम के अनुसार एक टीके की बिक्री पर आधी रकम उसे रायल्टी के रूप में एस्ट्राजेनेका को देनी पड़ती है। यह उसके लिए घाटे का सौदा है। इसलिए वह राज्यों को अपना टीका 300 रुपये और निजी क्षेत्र को उससे अधिक दाम पर बेचना चाहती है ताकि केंद्र सरकार को 150 रुपये में बेचने पर हुए घाटे की भरपाई कर सके। इसमें से 75 रुपये तो उसे एस्ट्राजेनेका को रायल्टी की मद में देने पड़ेंगे। यह रायल्टी हमें इसलिए देनी पड़ रही है, क्योंकि हमने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत उत्पाद पेटेंट कानून स्वीकार किया हुआ है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी द्वारा पेटेंट किए गए किसी भी उत्पाद को हम अपने देश में नहीं बना सकते। पेटेंट कानून के कारण वैक्सीन महंगी है और संपूर्ण विश्व को उपलब्ध भी नहीं हो पा रही। यदि हम पेटेंट कानून के दायरे में न होते तो सीरम के अलावा अन्य कंपनियां भी इस टीके को बना सकती थीं।

भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन भी केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत बायोटेक भी एस्ट्राजेनेका की तरह दूसरी देसी एवं विदेशी कंपनियों से रायल्टी वसूल कर सकती है। स्पष्ट है कि पेटेंट कानून के कारण देश में वैक्सीन का उत्पादन केवल दो कंपनियों द्वारा किए जाने से यह आसानी से जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पेटेंट कानून में व्यवस्था है कि आपदा काल में सरकार किसी पेटेंट को कुछ समय के लिए निरस्त कर सकती है और संबंधित वस्तु को बनाने का लाइसेंस किसी को भी दे सकती है। इस प्रकार भारत सरकार चाहे तो एस्ट्राजेनेका, रूसी स्पुतनिक, अमेरिकी फाइजर और भारत बायोटेक अथवा किसी अन्य देश की वैक्सीन बनाने के लाइसेंस अपने उत्पादकों को दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करने से हिचक रही है। यदि सरकार ने ऐसा किया तो विश्व की तमाम कंपनियां विरोध में आ जाएंगी। भविष्य में हमें इससे कठिनाई हो सकती है। इसलिए इस मामले में हमें सरकार के विवेक पर विश्वास करना पड़ेगा। मूल समस्या फिर भी पेटेंट कानून की है। 1995 में जब डब्ल्यूटीओ संधि हुई थी तो हमें विश्वास दिलाया गया था कि पेटेंट कानून से हुए नुकसान की भरपाई खुले व्यापार से हो जाएगी। विशेषकर हमारे किसानों के लिए विकसित देशों का बाजार खुलने से। इस बीच 25 वर्ष भी बीत गए, लेकिन विकसित

देशों ने येन-केन-प्रकारेण अपने बाजार हमारे कृषि उत्पादों के लिए बाधित कर रखे हैं। इसलिए डब्ल्यूटीओ हमारे लिए घाटे का सौदा रह गया है। पेटेंट कानून के कारण हम आधुनिक तकनीक की नकल नहीं कर पा रहे और वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। इस कारण संकट है। दूसरी ओर खुले व्यापार में हमें अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा। इसलिए इस आपदा को आधार बनाकर केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ पेटेंट कानून को निरस्त कर देना चाहिए। 1995 के पहले पेटेंट कानून में उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था थी यानी किसी भी माल को कोई भी उद्यमी बना सकता था, बशर्ते उसे बनाने में वह उस प्रक्रिया का पालन न करे जिस प्रक्रिया से पेटेंट धारक ने उस माल को बनाया है। जैसे कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका ने किसी विशेष प्रक्रिया से बनाया है। उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत कोविशील्ड को भारत के उद्यमी बना सकते हैं, बशर्ते वे उसे किसी दूसरी प्रक्रिया से बनाएं। यूं समझिए कि लोहे की सरिया को यदि एस्ट्राजेनेका ने गर्म करके पतला किया तो उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत उसी सरिया को हथौड़े से पीटकर पतला करने का हमें अधिकार था। यदि हम डब्ल्यूटीओ के प्रोसेस पेटेंट को निरस्त कर देते हैं तो विश्व की अन्य कंपनियों के टीके बनाने में स्वतंत्र हो जाएंगे, बशर्ते उनके द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग न करें। कोविड महामारी के बावजूद पेटेंट कानून बनाए रखने के पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला यही कि यदि पेटेंट निरस्त भी कर दिए जाएं तो भारत के पास वैक्सीन बनाने की क्षमता नहीं है। दूसरा यह कि उसमें लगने वाले कच्चे माल उपलब्ध नहीं हैं। तीसरा कि हमारे पास उत्पादन करने के लिए निवेश करने की क्षमता नहीं है। यह भी तर्क है कि पेटेंट कानून को निरस्त करने के स्थान पर हमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ मोलभाव कर उनसे लाइसेंस लेकर उनकी वैक्सीन का उत्पादन करना चाहिए। जैसे सीरम ने एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस लिया है। ये तर्क कहीं नहीं टिकते। यदि हमारे पास क्षमता ही नहीं है तो पेटेंट निरस्त करने से बड़ी कंपनियों को नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए पेटेंट को निरस्त कर देना चाहिए और दवाओं समेत देश को पेटेंट कानून के कारण जो भारी नुकसान हो रहा है, उससे निजात पानी चाहिए। फिलहाल कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। जिस प्रकार फ्लू का वायरस हर वर्ष म्यूटेट करता है और हर वर्ष उसका नया टीका बनता है, उसी प्रकार आने वाले समय में हर वर्ष कोविड के नए टीके का आविष्कार एवं उत्पादन करना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए भारत को अपने टीके बनाने के लिए भारी निवेश करना चाहिए। भारत बायोटेक के अनुसार उन्होंने कोवैक्सीन का आविष्कार मूलतः अपनी आर्थिक ताकत के आधार पर किया है। सर्वप्रथम सरकार को अपनी फार्मा कंपनियों को नए टीके विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे भविष्य में पैदा होने वाले वायरस के नए प्रतिरूपों का सामना करने के लिए हमारे पास टीकों की पर्याप्त शृंखला उपलब्ध हो। दूसरे सरकार को भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के पेटेंट को खरीद कर उसके फार्मूले को भारत की कंपनियों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को उपलब्ध करा देना चाहिए जिससे कोवैक्सीन का उत्पादन सारे विश्व में हो और हम बड़ी कंपनियों की मुनाफाखोरी को मात दे सकें। तीसरे, हमें डब्ल्यूटीओ को उत्पाद पेटेंट को लागू करने का प्रस्ताव देना चाहिए और डब्ल्यूटीओ न माने तो मुनाफाखोरी की संरक्षक इस संस्था से बाहर आ जाना चाहिए।

प्रशासन भीड़ पर सख्ती बरते और करे तालाबंदी, लॉकडाउन स्थायी हल नहीं

कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को किंकर्तव्यविमूढ़ कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु कोई भी इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है कि कुछ समय पूर्व जो स्थिति नियंत्रण में थी, वह यकायक अनियंत्रित कैसे हो गई? इसमें संदेह नहीं कि एक वर्ग महामारी की वर्तमान विकरालता का जिम्मेदार सरकारी व्यवस्थाओं को ठहरा रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया में जब महामारी का कोई भी रूप मानवीय विध्वंस करता है तो चारों तरफ आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। यह प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है। सफलता का श्रेय लेने के लिए सभी तत्पर रहते हैं और असफलताओं की जिम्मेदारी लेने का साहस किसी में नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि समाज का एक अभिन्न भाग होने के कारण सफलताओं और विफलताओं में हमारी सामूहिक भूमिका होती है। सरकारें क्या कर सकती हैं और सरकार की क्या खामियां हैं? आज चारों ओर विमर्श का विषय यही है। ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु कहीं कोई यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि व्यवस्थागत कमियों से इतर कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, जिसे निभाने में हमसे भारी चूक हुई है। दुनिया में जब कोविड-19 की पहली लहर ने दस्तक दी थी तो कोई समझ ही नहीं पाया था कि यह सब क्यों और किन कारणों से हो रहा? महामारी के अचानक हमले के लिए कोई तैयार नहीं था। नतीजतन सरकारों ने कठोर लॉकडाउन सहित कई कदम उठाए। उससे अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, परंतु ज्यादा जरूरी था मानवीय जीवन की रक्षा। दुनिया भर में जिन सरकारों ने लॉकडाउन में देरी की वहां अधिक जानें गईं, परंतु पिछले साल और वर्तमान में महामारी के स्वरूप में जो अंतर है वह व्यवस्थागत से कहीं अधिक हमारी जागरूकता की विफलताओं का है, क्योंकि अभी तक हम सब जान चुके हैं कि कोविड-19 क्या है, उससे लड़ने और बचाव के तरीकों से भी लगभग सभी परिचित हो चुके हैं। हमारी विफलता हमारी घोर लापरवाही है। ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है, जो यह मानकर चल रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता इसलिए न तो उन्हें वैक्सीन की जरूरत है, न मास्क की और न ही शारीरिक दूरी की। ऐसे लोगों की तादाद भी खूब है, जो वैक्सीन लगवाने के बाद स्वयं को कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित मान बैठे। प्रश्न यह उठता है कि क्या बिना मास्क के प्रयोग, साफ-सफाई की अवहेलना और शारीरिक दूरी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य संसाधनों पर निर्भर रहा जाए। ऐसा विकासशील देशों में ही नहीं, विकसित देशों में भी संभव नहीं है। अमेरिका स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1918-19 में स्पेनिश फ्लू के अध्ययन में पाया कि उस महामारी से दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई थी। उस दौरान भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, मरीजों को पृथक रखना और साफ-सफाई जैसे उपाय बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी साबित हुए थे। अमेरिका के सैनफ्रांसिस्को, सेंट लुइस, मिलवाको और कंसास में उन शहरों के मुकाबले मृत्यु दर में 30 से 50 प्रतिशत की कमी रही, जहां एहतियाती कदम बाद में उठाए गए। आत्मानुशासन और स्वचेतना से इतर हम प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह भीड़ पर सख्ती बरते और कोरोना को रोकने के लिए तालाबंदी करे। क्या यह न्यायोचित होगा, क्योंकि बीते साल तालाबंदी ने तमाम लोगों का रोजगार छीन लिया था। लॉकडाउन स्थायी हल नहीं हो सकता। कोरोना खत्म होने में कितना समय लगेगा, वैज्ञानिक इस पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए कोरोना के प्रति सावधानी बरतना और उस मार्ग को अपनाना जरूरी हो जाता है, जहां मानव जीवन की रक्षा के साथ-साथ जीविकोपार्जन के साधनों पर भी कुठाराघात न हो।

लैजरेटो इन ड्यूब्रोन्विक ־ द बिगनिंग ऑफ द क्वारंटाइन रेगुलेशन इन यूरोप' नामक एक शोध में वर्तमान परिस्थितियों का हल दिखाई देता है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैले प्लेग को रोकने के लिए तत्कालीन रगुजा (आधुनिक ड्यूब्रोन्विक) की महापरिषद ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए 1377 में एक कानून बनाया, जिसके मुताबिक रगुजा आने वाले हर जहाज और व्यापारियों के काफिले को 30 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होता था। ड्यूब्रोन्विक ने इस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना महामारी को फैलने से रोकने में सफलता पाई।

दूसरी तरफ उसी समय वेनिस में सभी जहाजों और व्यापार पर रोक लगा दी गई। इससे वहां का जीवन और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। स्वाभाविक रूप से इसका प्रत्यक्ष और नकारात्मक प्रभाव वहां के नागरिकों पर पड़ा। कोरोना की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए देश में इस समय सबसे अधिक जरूरत घरेलू स्तर पर संवाद को मजबूत बनाने की है। साथ ही ऐसे बहुआयामी पक्षों को सामने लाने की भी है, जिससे इस महामारी का मुकाबला सकारात्मकता को बनाए रखते हुए किया जा सके। वर्तमान परिदृश्य में 'रिटोरिकल अरीना थ्योरी' कारगर सिद्ध हो सकती है। यह संवाद का वह तरीका है, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्र के लोग एवं संकट से निपटने में जुड़े तमाम विभाग अपने-अपने तरीके से जनता से ऐसे संवाद करते हैं कि उनके बीच आपसी समन्वय बना रहे। लॉकडाउन के बगैर स्वयं को अनुशासित करके महामारी से लड़ने की तैयारी हमें करनी ही होगी, वरना आने वाले समय में लोग दूसरी अघोषित महामारी अवसाद के शिकार हो जाएंगे,

तालमेल से बनेगी बात

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन पॉलिसी पर अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि महामारी से कैसे निपटना है, यह कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। सरकार की दलील है कि चूंकि कोर्ट की इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उसकी दखलंदाजी, नेक इरादों के बावजूद बेहद गंभीर नतीजों को जन्म दे सकती है। सिद्धांत रूप में केंद्र सरकार के इस रुख से असहमत होना मुश्किल है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र बंटे हुए होते हैं और यह स्थिति हमेशा अच्छी मानी जाती है कि तीनों अपना-अपना काम पूरी निष्ठा से करते हुए दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से बचे रहें। आम तौर पर ऐसा होता भी है। समस्या कुछ खास स्थितियों में होती है, जब या तो तीनों में से कोई अंग अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाता या फिर किसी का दायित्व बोध उसे उस मामले में भी कुछ कहने-करने को मजबूर करता है, जिसे दूसरा अंग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। मौजूदा मामला इसी दूसरी श्रेणी का है, जिसमें कोरोना की बेकाबू हुई दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सिजन और दवाओं के अभाव में असहाय देख न्यायपालिका को लगा कि वह मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। वैक्सीन की कीमतों से जुड़े मौजूदा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सुओमोटो सुनवाई शुरू की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं है। उसने यह साफ कर दिया था कि उसका इरादा किसी भी रूप में सरकार की नीति की जगह अपनी नीति देने का नहीं है। हां, उसने सरकार की नीति को लेकर कुछ चिंताएं जरूर जाहिर कीं। ये चिंताएं सिर्फ न्यायपालिका की नहीं हैं। समाज के अलग-अलग हिस्से इन सवालों को स्वर देते रहे हैं। उदाहरण के लिए, यह आशंका कई लोगों ने जाहिर की है कि वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों का बुरा असर वैक्सिनेशन कार्यक्रम पर पड़ सकता है। यही नहीं, महामारी के अन्य पहलुओं पर भी सरकार की तैयारी और उसके रिस्पॉन्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकारी तंत्र मरीजों की जान बचाने में लगे अस्पतालों तक जरूरी सुविधाएं और आवश्यक दवाएं, इंजेक्शन, ऑक्सिजन आदि समय से पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, यह तो है ही, इसकी शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी उदाहरण देखे गए हैं। ऐसे में अदालतें अगर आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में आगे आती हैं तो अपना कर्तव्य ही पूरा करती हैं। बहरहाल, इसमें संदेह नहीं कि महामारी से कुशलता से निपटना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और संकट के इस दौर में शासन के बाकी सभी अंगों की भूमिका उसे इस जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में मदद देने की ही हो सकती है,

हिंसा रोकने में ममता की कोई दिलचस्पी नहीं, रक्तरंजित बंगाल कलंकित होने को विवश

राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ-साथ लेफ्ट-लिबरल बिरादरी के लिए ममता की जीत ही लोकतंत्र की सच्ची जीत है। यह बिरादरी बंगाल में ममता की जीत के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के लिए उपयुक्त चेहरा बताने में जुट गई है। हो सकता है कि ममता वाकई राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश करें, लेकिन बंगाल को तबाह होने से कोई नहीं रोका सकता-शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं।
यदि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर बंगाल की हिंसा का संज्ञान लेता भी है तो लेफ्ट-लिबरल बिरादरी उस पर वैसे ही टूट पड़ेगी, जैसे तृणमूल कार्यकर्ता अपने विरोधियों पर टूट पड़े हैं। निन्संदेह ममता चुनाव बाद की हिंसा को रोक सकती थीं, लेकिन तब, जब इसमें उनकी कोई दिलचस्पी होती।

किसी की चुनावी जीत कितनी घिनौनी हो सकती है, इसका शर्मनाक और खौफनाक उदाहरण है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की ओर से मचाया जा रहा भीषण उत्पात। तृणमूल के नेता और कार्यकर्ता चुनाव नतीजे आते ही राजनीतिक विरोधियों पर जिस तरह टूट पड़े हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं पर चुन-चुनकर हमले हो रहे हैं। उनके दुकान-मकान लूटे जा रहे, उनमें आगजनी की जा रही है। महिलाओं, बच्चों और वृद्धों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रत्याशियों तक को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस या तो उनकी मदद करना नहीं चाहती या फिर ऐसा करने में असहाय है। चूंकि ऐसी कई घटनाएं पुलिस की उपस्थिति में हुई हैं इसलिए इसमें संदेह नहीं कि यह हिंसा प्रायोजित है। इसकी आशंका पहले से थी, क्योंकि बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए अर्से से कुख्यात है। वहां चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई थी। यह हिंसा चुनाव के दौरान भी जारी रही और वह भी तब, जब मतदान आठ चरणों में कराया गया।

चुनाव बाद भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा होने का अंदेशा था। इस अंदेशे को खुद बल दिया था ममता बनर्जी ने। एक सभा में उन्होंने कहा था, आखिर कितने दिन रहेंगे केंद्रीय बल? उनके जाने के बाद हम देख लेंगे। लगता है उन्होंने सचमुच देख लिया। क्या उनका आशय अपने कार्यकर्ताओं की हिंसा से था? पता नहीं,

लेकिन यह तथ्य है कि उन्हें यह हिंसा दिख नहीं रही। उनकी और उनके सहयोगियों की मानें तो राजनीतिक हिंसा की खबरें फेक न्यूज हैं। उनकी ओर से यह तो नहीं कहा जा रहा कि बंगाल में सब अमन-चैन है, लेकिन प्रतीती ऐसी ही कराई जा रही है।

तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जारी भयानक हिंसा को जायज भी ठहराने में लगे हुए हैं। उसके सांसद डेरेक ओ ब्रायन कह रहे हैं कि दरअसल भाजपा के लोग ही आपस में एक-दूसरे को पीटकर हार की खीझ निकाल रहे हैं। ब्रायन की मानें तो भाजपा के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पार्टी की धाकड़ नेता कही जाने वाली सांसद महुआ मोइत्रा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट से अविचलित हुए बगैर नसीरुद्दीन शाह के एक कथित कथन के सहारे पूछ रही हैं, सवाल यह है कि पागल के हाथ माचिस किसने दी? ब्रायन और महुआ की हां में हां मिलाने का काम तथाकथित बुद्धिजीवी और लिबरल पत्रकार भी उत्साह से कर रहे हैं। एक ने तो ट्वीट भी कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। जब लानत-मलानत हुई तो सफाई दी कि इतने बजे मेरा एकाउंट हैक हो गया था। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं। इस तरह के लोग होते हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हें और खासकर लेफ्ट-लिबरल तत्वों को विपरीत विचार वालों का दमन आनंदित करता है। वे अंध समर्थन या अंध विरोध में अपनी ही विचारधारा के बंधक होते हैं और कहीं कोई कितना भी गलत काम हो, उसे सीधे-सीधे या फिर कतु-परंतु के साथ जायज ठहराते हैं। विडंबना यह कि ऐसे बुद्धिजीवियों, पत्रकारों से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वे बंगाल की हिंसा पर कुछ बोलते क्यों नहीं? भला वे क्यों बोलेंगे? वे तो ऐसा ही कुछ होते हुए देखना चाहते थे।

इसकी भी अनदेखी न करें कि मीडिया के एक हिस्से को बंगाल में राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा कभी नजर ही नहीं आती। बंगाल के मीडिया को तो इस तरह की हिंसा को नजरअंदाज करने में महारत हासिल है। याद करें कि जब मालदा, बशीरहाट, आसनसोल की हिंसा का देश भर का मीडिया संज्ञान ले रहा था, तब बंगाल का मीडिया मौन था। बंगाल का परंपरागत मीडिया एक अर्से से इस पर बहस कर रहा है कि हमें हिंसा और खासकर राजनीतिक-सांप्रदायिक हिंसा की खबरें देनी चाहिए या नहीं? वह बार-बार इसी नतीजे पर पहुंचता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि कोलकाता के बगल में भयानक हिंसा होती है, लेकिन कोलकाता के ही बड़े अखबारों में उसके बारे में एक पंक्ति का समाचार नहीं होता।

इसमें संदेह है कि बंगाल की राजनीतिक हिंसा थमेगी, क्योंकि एक तो तृणमूल को वह दिख ही नहीं रही और दूसरे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जिन दलों के कार्यकर्ता मारे-पीटे जा रहे हैं उनका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है? तृणमूल कांग्रेस की समझ से विरोधी दलों के नेता अपनी हार के बाद बंगाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भी तृणमूल की हिंसक भीड़ का शिकार बन रहे हैं, लेकिन उनकी हालत इसलिए सबसे दयनीय है, क्योंकि राहुल गांधी इससे खुश हैं कि ममता ने भाजपा को हरा दिया। राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ-साथ लेफ्ट-लिबरल बिरादरी के लिए ममता की जीत ही लोकतंत्र की सच्ची जीत है। यह बिरादरी बंगाल में ममता की जीत के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के लिए उपयुक्त चेहरा बताने में जुट गई है। हो सकता है कि ममता वाकई राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश करें, लेकिन बंगाल को तबाह होने से कोई नहीं रोका सकता-शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं।

यदि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर बंगाल की हिंसा का संज्ञान लेता भी है तो लेफ्ट-लिबरल बिरादरी उस पर वैसे ही टूट पड़ेगी, जैसे तृणमूल कार्यकर्ता अपने विरोधियों पर टूट पड़े हैं। निन्संदेह ममता चुनाव बाद की हिंसा को रोक सकती थीं, लेकिन तब, जब इसमें उनकी कोई दिलचस्पी होती। अगर उनकी दिलचस्पी होती तो बंगाल में खेला होबे के बाद इतना खुलकर खून-खराबा नहीं होता और न ही रक्तरंजित बंगाल कलंकित हो रहा होता।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

उत्तर प्रदेश में नदियों में शव मिलने का सिलसिला जारी, खतरे में पड़ा मिशन नमामि गंगे

लखनऊ । कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लोगों के साथ ही अब देश तथा प्रदेश की जीवनदायिनी माने जाने वाली गंगा नदी पर भी बड़ा संकट गहरा रहा है। मोक्षदायिनी माने जाने वाली गंगा नदी के साथ ही यमुना, गोमती तथा अन्य नदियों या फिर उनके तट पर रोज सैकड़ों शव मिल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से मृत लोगों के परिवार के लोग या तो इनके शवों को बहा दे रहे हैं या फिर आधे जले शवों को नदी के पास छोड़कर इतिश्री कर ले रहे हैं।

इसके बाद की सारी कसर सरकारी नुमाइंदे, घाट पर रहने वाले लोग या फिर जानवर कर दे रहे हैं। प्रदेश में बीते एक हफ्ते से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है। हमीरपुर तथा महोबा में यमुना नदी हो या फिर बदायूं से लेकर बलिया तक गंगा नदी में शव लगातार मिलते ही जा रहे हैं। नदी के अलावा लोग नहरों में भी शवों को फेंकने में संकोच नहीं कर रहे हैं। इनको शायद अंदेशा नहीं है कि उन्होंने जो काम बला समझ के किया है, वह उनके ही सिर पर पड़ेगा।

कानपुर तथा उन्नाव में घाट पर जगह न मिलते देख लोग गंगा नदी के किनारे ही शवों दो ठिकाने लगा दे रहे हैं। तेज हवा चलने के बाद तो दफन सारे शव ऊपर आने लगे हैं। दफन करने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शवों को सीधा बहा दे रहे हैं। इनमें भी 90 प्रतिशत से अधिक शव कोरोना वायरस संक्रमण से मृत लोगों के हैं। उन्नाव के बाद लोग कानपुर में भी शव दफन कर रहे हैं। खेरेश्वर घाट पर लोग कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के शवों को दफन कर रहे हैं। सरकार के अंत्येष्टि के लिए पांच हजार रुपया प्रति शव देने की घोषणा सिर्फ कागजों पर ही है। कानपुर के साथ उन्नाव में गंगा नदी की रेती में शव मिल रहे हैं। उन्नाव तथा कानपुर के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद स्वजन बड़ी लापरवाही कर रहे हैं।

वाराणसी और पास के जिलों बलिया, गाजीपुर और चंदौली में भी शवों का नदी में प्रवाहित करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बलिया तथा गाजीपुर में शवों को प्रवाहित करने पर रोक के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। वाराणसी में आज चार शव मिले हैं। गंगा नदी के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार को चार शव उतराते मिले हैं।

उधर गाजीपुर में भी गंगा व गोमती नदी में बड़ी संख्या में शव मिलने के बाद डीएम ने कहा कि अब नदियों में शवों के जल विसर्जन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच बिहार बॉर्डर पर बक्सर पुलिस ने गंगा नदी में जाल लगाया है, जिससे कि बलिया से आने वाले शव को रोका जा सके। वाराणसी में नाविकोंके साथ प्रातः व सांयकाल गंगा नदी के तट पर आने वाले

लोग शवों के दुर्गंध से परेशान है। उनका कहना है पहले गंगा नदी में शव प्रवाहित नहीं कि, जाते थे। नाविकों का दावा है कि गंगा उस पार से कोरोना संक्रमित शवों को जल प्रवाहित किया जा रहा है। गाजीपुर के डीएम ने कहा शवों के अंतिम संस्कार में निर्धन व असहायों की आर्थिक मदद होगी। शवों का जल विसर्जन अब नहीं होगा। हर नदी के किनारों पर पुलिस की पैनी नजर है और निगरानी की जा रही है। सभी श्मशान घाटों पर पुलिस टीम ने मुनादी की है।

शव की अंत्येष्टि भी समाज सेवा- नदियों में शव कहां से बहकर आ रहे हैं, इस प्रश्न पर हर जिम्मेदार पल्ला झाड़ ले रहा है। शव आसमान से तो टपक नहीं रहे हैं। इससे पहले तो ऐसा होता भी नहीं था, फिर अचानक से भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में शवों का मोक्षदायिनी में बहना इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। शब्द भी नहीं हैं कि गंगा नदी में और किनारे किनारे मिले अब तक हजारों शवों की दुर्दशा को क्या कहे। इन सभी का विधिवत अंतिम संस्कार तो किया ही जाना चाहिए। सदियों से गंगा बह रही है, लेकिन आज तक गंगा के किनारे बसे गांव वालों ने इस तरह इंसानियत को तार-तार करने वाला मंजर कभी नहीं देखा होगा। जिंदा के साथ ही किसी भी मृत को सम्मान देना भी समाज सेवा का ही हिस्सा है।

कोरोना काल में बड़ा होता गया शमशान घाट का दायरा- कोरोना वायरस से संक्रमण में बड़ी संख्या में मौत के मामलों से श्मशान घाट का दायरा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बीती रात बारिश के बाद गंगा नदी का हल्का सा जल बढ़ा कि उन्नाव व कानपुर में शमशान घाट का बड़ा दायरा बेहद छोटा हो गया। गंगा का जलस्तर क्या बढ़ा, कई शव बाहर आ गए। इन सभी को स्वजन रेत में दबाकर चले गए थे। इसके बाद तो वहां का दृश्य बेहद ही वीभत्स हो गया था। कुत्तों का झुंड उनपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर बाद वहां शव के टुकड़ों का अंबार और क्षत-विक्षत मानव अंग पड़े थे।

कम पडने लगी लकडियां - कोरोना संक्रमण के कारण इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। महानगरों में तो संक्रमितों की अंत्येष्टि विद्युत शवदाह गृह में की जा रही थी, लेकिन इतनी लम्बी लाइनें देखकर स्वजन भयभीत होने लगे और शार्टकट ढूंढा गया, जो आजकल नदी के तट पर या फिर नदियों में दिख रहा है। अंत्येष्टि के लिए लड़कियां कम पडने लगीं और इसी में पैदा हो गए आपदा के असुर। जिन्होंने सैकड़ों का काम हजारों रुपया लेकर किया। सभी लोग सक्षम नहीं थे और उन लोगों को नदी का सहारा मिला।

बिहार के बक्सर में गंगा नदी में उतराते बड़ी संख्या में शवों के मामले में बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की थी। बिहार सरकार का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बलिया तथा गाजीपुर के शव बहकर आ रहे हैं। अब जो भी कार्रवाई करनी है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी है, हमें उम्मीद है प्रदेश सरकार बहुत जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगी।

औरैया में यमुना नदी में बहते मिले अधजले शव : यमुना नदी में पहले तो हमीरपुर और अब औरैया जिले में बड़ी संख्या में अधजले शव बहते मिले हैं। गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण या फिर अन्य बुखार के कारण मौत के बाद लोग नदी के तट पर काफी जल्दबाजी में शवों की अंत्येष्टि करने के प्रयास में रहते हैं। जिसके कारण बड़ी संख्या में शव अधजले ही रह जाते हैं। लोग अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूरी होने से पहले चले जाते हैं। यह सभी लोग संक्रमण के डर से चले जाते हैं तो बाद में आने वाले लोग अधजले शव को नदी में बहा देते हैं। इतना ही नहीं कई जगह पर तो शवों को सीधा नदी में ही प्रवाहित कर दिया जा रहा है। इसके बाद कई घाटों पर नदी के तेज बहाव के कारण शव नदी के किनारे आ रहे हैं। औरैया के शेरगढ़ शमशान घाट पर यमुना नदी के किनारे आने वाले शवों को कुत्ते भी नोंचते दिखते हैं।

बरेली में रामगंगा में मिले दो शव: बरेली में रामगंगा नदी में भी सुबह फतेहगंज पूर्वी में रामगंगा में दो शव दिखे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी से बाहर निकाला। आशंका जताई गई कि कोरोना पीड़ितों के शव हो सकते हैं, जो किसी ने सीधा नदी में बहा दिया है। डीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार शवों को दफनाया गया। पुलिस रामगंगा घाट पर दुकानदार, नाविकों से पूछताछ कर रही कि किसी अस्पताल की एम्बुलेंस तो देर रात नहीं आई।

सीएम योगी ने लिया संज्ञान: उत्तर प्रदेश में नदियों में बहाए जा रहे शवों के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेने के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत पर दुःख जताया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल में नदियों से मिल रहे शवों के मामले में कहा कि अंत्येष्टि की क्रिया मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मृतक की अंत्येष्टि के लिए जल प्रवाह की प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सभी की अंत्येष्टि क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर ने चांदी कारोबारी को धमकाकर हड़पे 43 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज

आगर । मथुरा के एक चांदी कारोबारी से वाणिज्यकर के असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम ने धमकाकर 43 हजार रुपये हड़प लिए। मुंह खोलने पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी। व्यापारी ने घटना के 12 दिन बाद मामले की शिकायत एसएसपी से की। इसके बाद बुधवार रात लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

मथुरा के गोविंद नगर में महाविद्या कालोनी निवासी प्रदीप अग्रवाल की विनायक ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। वे श्रीहरि कांप्लेक्स गुड़हाई बाजार से चांदी के गहनों का व्यापार करते हैं। 22 अप्रैल को प्रदीप अपनी गाड़ी से चालक राकेश चौहान के साथ व्यापार के संबंध में बिहार के कटिहार गए थे। वहां 44 लाख रुपये की बिक्री की थी। इनमें से 43 लाख रुपये एक थैले में भरकर उन्होंने गाड़ी में रख लिए। एक लाख रुपये जेब में रखकर वे मथुरा के लिए गाड़ी से निकल लिए। 30 अप्रैल की रात 10.15

बजे वे लखनऊ एक्सप्रेस वे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहां फास्ट टैग लेन से उनकी गाड़ी निकलने वाली थी। तब तक एक सिपाही सामने आ गया। उसने चालक से कहा कि गाड़ी साइड में लगाकर साहब के पास चलो। उप्र सरकार लिखी बोलेरो गाड़ी में बैठे साहब ने चालक को अपने पास बैठा लिया। सिपाही प्रदीप की गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी लेकर जीएसटी कार्यालय चलने को कहा। थोड़ी देर में ही वे लोहामंडी में स्थित जीएसटी कार्यालय लेकर पहुंच गए। प्रदीप का आरोप है कि वहां पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में रखे 43 लाख रुपये से भरे थैले को निकाल लिया और कहने लगे कि इसे आयकर विभाग को सौंपेंगे। इसके बाद पूछने लगे कि गाड़ी में चांदी कहां रखी है? प्रदीप ने उन्हें समझाया कि यह रुपये वे चांदी के गहने बेचकर ही लाए हैं, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कारोबारी से कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो थैले में रखे रुपयों को भूल जाओ। यह भी कहा कि अगर यह बात किसी को बताई तो झूठे मुकदमे लिखा देंगे। रात 12.45 बजे कारोबारी और चालक को छोड़ा गया। इस घटना से वे डर गए थे। तीन दिन बाद उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत को पूरा मामला बताया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर इसकी शिकायत की। इसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई। बुधवार को प्रदीप अग्रवाल ने एसएसपी मुनिराज जी से मामले की शिकायत की। उनके आदेश पर बुधवार रात लोहामंडी थाने में अज्ञात साहब, चपरासी, सिपाही और चालक के खिलाफ अमानत में खयानत और धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

गुरुवार को इस मामले में वाणिज्यकर कमिश्नर मिनिस्ती एस ने घटना में शामिल अधिकारियों के नाम मुकदमे में शामिल कराने को पत्र भेजा। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि विभागीय जांच में सामने आया है कि असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर अजय कुमार, वाणिज्यकर अधिकारी शैलेंद्र कुमार, आरक्षी संजीव कुमार, और प्राइवेट गाड़ी का चालक दिनेश कुमार घटना में शामिल थे। इन सभी के नाम विवेचना में खोलकर कार्रवाई की जाए। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब विभागीय जांच रिपोर्ट और वाणिज्यकर कमिश्नर का पत्र मिलने के बाद सभी के नाम मुकदमे में प्रकाश में लाए जा रहे हैं।

भारत में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रयागराज में परिवार के सदस्य एक संदिग्ध कोविड -19 पॉजिटिव मरीज को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में शिफ्ट करते हुए।

आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोविड कंट्रोल सेंटर का किया मुआयना

आगरा । राजकीय विमान से गुरुवार सुबह आगरा एयरपोर्ट पर पहुंच सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ चले गए थे। अलीगढ़ के बाद वे दोपहर करीब तीन बजे मथुरा आ चुके हैं। वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी से लंच के बाद मुख्यमंत्री सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वे मथुरा के कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे हैं। मथुरा के बाद मुख्यमंत्री आगरा करीब 4.30 बजे आए।

आगरा में खेरिया एयरपोर्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधे पथौली गांव गया। यहां कल से तैयारियां की जा रही थीं। गांव में मुख्यमंत्री ने लाचारीराम से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। लाचारीराम की पत्नी ने पंचायत चुनाव लड़ा था। लाचारीराम ने दो मई को कोविड टेस्ट कराया था, अब उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नगर निगम स्थित कोविड कंट्रोल रूम पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने एमजी रोड पर यातायात को कुछ देर के लिए रोक दिया था। कोविड कंट्रोल सेंटर के बाद सीएम एसएन मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। नगर निगम की कार्यकारिणी कक्ष में पुलिस-प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य अफसरों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7.25 बजे राजकीय वायुयान से आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

मथुरा में बोले सीएम, एक्टिव केसों में कमी- गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी दोपहर तीन बजे पहुंच गए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बहुत ही चुनिंदा लोग उनके साथ दौरे में शामिल हुए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें इंतजाम चाक चौबंद मिले। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि मुख्यमंत्री आगमन की सूचना पर बुधवार से ही जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर ध्यान दे दिया था। रात से लेकर आज दोपहर तक साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन के काम चलते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड से बचाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि सक्रिय केसों में तेजी से कमी आयी है। जिम्मेदार पदों पर बैठों लोगों को अनर्गल बयानबाजी नही करनी चाहिए। कोरोना वारियर्स और कोविड के कार्यों में लगे लोगों को हतोत्साहित न करें बल्कि उनका उत्साहवर्धन करें। सीएम ने यहां मरीजों से बातचीत भी की।

यूपी में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण 20 से 31 मई तक, अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड पर मिलेगा राशन

लखनऊ । कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में दो माह मई और जून में निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में आगामी 20 मई से 31 मई तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने गुरुवार को जारी किए आदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर दो माह मई और जून में पांच किलोग्राम प्रति यूनिट के अनुसार निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई के मध्य मान्य होगी। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि दुकानों पर भीड़ न जुटने पाए इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू होगी। आधार प्रमाणीकरण के जरिए खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ता के लिए मोबाइल फोन पर ओटीपी वेरीफिकेशन से राशन प्राप्त करने का अवसर होगा। वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होने देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। निशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रचारित भी करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। इसी के तहत प्रदेश में 20 मई से मुफ्त राशन बंटेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 14 मई तक राशन का वितरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 86 प्रतिशत बढ़ा, 24 घंटे में 17775 नए केस और 286 की मौत

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन के चरम पर आने के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का बेहद ही कारगर असर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके साथ ही रोज टीम-9 के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण के कारण सरकारी मशीनरी भी मिशन मोड पर आ गई और अब प्रदेश में रिकवरी रेट 86 प्रतिशत बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 17775 नए संक्रमित केस मिले हैं। इस दौरान 286 की मौत भी हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस दो लाख 4658 हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में बीते दो दिन से नए संक्रमितों की संख्या में भले ही कुछ कमी आ रही है, लेकिन

मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटों में 281 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से दम तोड़ा है, जबकि अब तक कुल 16,646 मौतें हुई हैं।

नए संक्रमित केस में कमी, मौतों की संख्या में बढ़ोतरी- कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बेहद ही घातक है। इसमें मृतकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी लखनऊ में भले ही नए संक्रमित मिलने के मामले में 900 की कमी आ गई है, लेकिन बीते 24 घंटे में 35 लोगों ने दम तोड़ा है। लखनऊ में अब एक्टिव केस 16117 हैं जबकि कुल 2194 की मौत हो चुनी है। लखनऊ में आज 856 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक नए संक्रमित 1070 मेरठ में मिले हैं। यहां पर 15 लोगों की मौत हुई है। कानपुर नगर में 288 नए केस मिले जबकि 16 ने दम तोड़ा। गौतमबुद्धनगर में 747 केस मिले और 11 की मृत्यु हो गई। झांसी में 354 नए संक्रमित मिले तो दस की मौत हो गई। मुरादाबाद में 504 नए केस मिले हैं तो यहां छह का निधन हो गया। गोरखपुर में 775 और वाराणसी में 772 नए संक्रमित मिले हैं। गोरखपुर में नौ और वाराणसी में छह की मौत हुई है। प्रयागराज में 240 नए संक्रमित मिले हैं, यहां पर पांच लोगों ने दम तोड़ा है।

महोबा में तो मामला बेहद ही विचित्र है। यहां पर आठ नए संक्रमित मिले हैं तो दस लोगों ने जान गंवा दी है। इसी तरह से बहराइच में 109 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 12 लोगों का निधन हो गया है। गाजीपुर में दस लोगों ने दम तोड़ा है जबकि यहां पर 364 नए संक्रमित केस मिले हैं।

जाप सुप्रीमो की पत्नी रंजीत का बड़ा ऐलान, दो दिन में जेल से रिहा नहीं हुए पप्पू यादव तो करूंगी अनशन

पटना । पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल भेजने के मामले में उनकी पत्नी व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी और ड्रग्स माफिया के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर दो दिनों में पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई, तो वे मुख्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी और भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। रंजीत रंजन गुरुवार को पटना में प्रेस से बात कर रही थीं।

रंजीत ने कहा कि महामारी में राजनीति राजनीति खेलने का वक्त नहीं है, इस वक्त हमसबों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। आज पप्पू यादव के साथ लोग इसलिए नहीं खड़े हैं कि चुनाव होने वाला है। या कोई बड़ी पार्टी है। आज लोग इसलिए खड़े हैं कि महामारी चल रही है। दूसरी लहर चल रही है। लोगों की जानें जा रहे हैं। सबलोग भयभीत हैं। मैं पूछना चाहती हूं पप्पू यादव का कौन सा अपराध था, जिसमें जेल भेजा गया। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किया गया। फिर बाद में 32 साल पुराने के केस में उन्हें जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया। किसलिए भेजा गया। कौन सा। अपराध था और वे कौन लोग हैं जिनके इशारे पर ये कार्रवाई हुई है।

भाजपा का पूरे देश में गुंडाराज चल रहा- रंजीत ने कहा कि नीतीश बाबू अगर आप इतने मजबूर थे, तो हमलोग को बता देते कि बहुत कम विधायक आये हैं। भाजपा का पूरे देश में गुंडाराज चल रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, जिसके दबाव में आप वो सबकुछ कर रहे हैं, जो बिहार को गवारा नहीं। बालिका गृह कांड है। क्या आपके केस हैं। 1991 में हत्या का केस हुआ 2011 में रफा। दफा करा लिया। 89 में जिस कांड में आपने पप्पू यादव पर केस हुआ। इस कांड का सूचक, आज तीनो लोगों का वीडियो चल रहा है कि केस फर्जी है। 32 साल बाद पुराना केस महामारी के वक्त याद आया क्यों? इसी में सब छुपा है।

ड्राइवरों को क्यों नहीं दी ट्रेनिंग

उन्होंने पूछा कि रूडी पायलट थे, किसके आशीर्वाद से मंत्री बने, कैसे राजनीति में आये। उत्तराखंड फार्म हाउस, बिहार, दिल्ली से लेकर जितने भी स्टाफ हैं, उसकी सैलरी कहां से दे रहे हैं। कांस्टीट्यूशन क्लब का इंचार्ज जब बनाया गया, तब कितना घोटाला हुआ। स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे और मोदी साहब ने क्यों हटाया। स्किल इंडिया में एम्बुलेंस ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी। ये सब आप बताएं।

सिवान जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से कमरे में मिले तेज प्रताप यादव, बोले- अपने परिवार में आया हूं

पटना । सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से नाराजगी की खबरों के बीच तेज प्रताप यादव गुरुवार की सुबह उनके घर पहुंचे। लालू के बड़े बेटे और प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप बुधवार को ही सिवान जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। गुरुवार की सुबह-सुबह तेज प्रताप पूर्व सांसद के पैतृक गांव प्रतापपुर स्थित उनके घर पहुंचे और उनके बेटे ओसामा से मुलाकात की। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब फिलहाल किसी नेता से मुलाकात नहीं कर रही हैं।

इसके पीछे इस्लाम की एक रस्म है, जिसकी वजह से वह किसी पुरुष से फिलहाल मुलाकात नहीं कर सकती हैं। शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में स्वजनों से मुलाकात करने के बाद तेजप्रताप पूर्व सांसद के सिवान के आनंद नगर स्थित आवास पर आए और यहां काफी देर तक ठहरे। यहां उन्होंने शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब के साथ काफी देर तक मुलाकात की।

यहां मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय और सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद रहे। तेज प्रताप ने कहा कि शहाबुद्दीन राजद और लालू परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे। यह उनका अपना परिवार है। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि उनके परिवार से दिल्ली में कोई क्यों नहीं गया, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

तेज प्रताप से पहले दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव भी सिवान में पूर्व सांसद के घर गए थे। उन्होंने भी ओसामा से मुलाकात की थी। उनके ठीक बाद जदयू नेता राधा चरण सेठ सिवान गए थे। सेठ पहले राजद में ही शामिल थे, लेकिन पिछले चुनाव से पहले उन्होंने खेमा बदल लिया। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से वे सिवान आए हैं, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं।

पटना विमेंस कॉलेज कैंपस में, कोविड -19 वैक्सीन की खुराक लेने के बाद, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी पटना में सेल्फी लेती हुई।

ठाणे के मुंब्रा में ईद उल-फितर त्योहार की पूर्व संध्या पर एक बाजार में महिलाएं आभूषण खरीदती हुई।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता अहमदाबाद में ड्राइव-थ्रू टीकाकरण केंद्र पर कोविड -19 वैक्सीन की एक खुराक देते हुए।

सोलापुर में कोविड -19 तालाबंदी के दौरान, भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीके की आपूर्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए।

एक नजर

सरकार ने विधानसभा में कहा-अनुसूचित जाति की महिलाओं से दुष्कर्म के दर्ज होते हैं झूठे मामले

जयपुर । राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में हीनियस क्राइम से जुड़े मामले बिना रोकटोक दर्ज होने के कारण लोग दलित महिलाओं के माध्यम से झूठे मुकदमें दर्ज करा दिए जाते हैं। इस कारण दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में साल, 2018 की तुलना में 2020 में 17.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल, 2018 से 2020 तक दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 1467 मुकदमें पुलिस में दर्ज हुए, जिनमें से 555 जांच में झूठे पाए गए। झूठे मुकदमें दर्ज करवाने पर तीन साल के दौरान 28 मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई के लिए कोर्ट में पुलिस ने इस्तगासे पेश किए हैं। इसके साथ ही 825 दुष्कर्म के मामलों में 1153 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चालान पेश किया गया। साल, 2018 में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 416 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 161 झूठे पाए गए। इसी तरह 2019 में 563 में से 214 और 2020 में 448 में से 180 मामले झूठे पाए गए। जवाब के अनुसार दलितों पर अत्याचार को लेकर 2018 से 2020 तक कुल 18,426 मामले दर्ज हुए। इनमें से 7731 मामले झूठे पाए गए। इन मामलों को पुलिस ने जांच के बाद बंद कर दिया। उधर, इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक का कहना है कि दलित महिलाओं से दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाओं में सामाजिक दबाव के कारण भी गवाह मुकर जाते हैं। सामाजिक दबाव के कारण कई बार शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं। इस कारण मुकदमों को बंद कर दिया जाता है। इन्हें झूठा करार दे दिया जाता है।

महीनों बाद घर लौटे पति को टोका तो क्रिकेट के बैट से पत्नी का सिर फोड़ ले ली जान

उदयपुर । राजस्थान में उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के गुंदाली पंचायत के मालियों की भागल गांव में गुरुवार दोपहर एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तीन महीने बाद घर लौटे युवक को उसकी पत्नी का टोकना नागवार गुजरा और गुस्से में आकर उसने क्रिकेट के बैट से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया है। ताबड़तोड़ हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दौरान बच्चों ने अपनी मां को बचाना चाहा तो उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा और मारपीट के बाद फरार हो गया है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा हमलावर पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मालियों की भागल गांव का रूपलाल गमेती गुरुवार को लगभग तीन महीने बाद अपने घर लौटा था। इस बीच, उसकी पत्नी भूरकी तथा उसके तीन बच्चे गांव में रह रहे थे। भूरकी ने अपने पति रूपलाल को कई महीनों तक लापता रहने को लेकर टोकाटाकी की तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया।

इसी दौरान रूपलाल आक्रोशित हो गया और घर में रखे क्रिकेट के बैट को उठाकर पत्नी भूरकी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर फटने से भूरकी निढ़ाल होकर गिर पड़ी तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान भूरकी के तीनों बेटों ने भी बीच-बचाव किया, लेकिन रूपलाल ने उन पर भी हमला कर दिया था। पत्नी के मरने पर वह घटनास्थल से भाग निकला। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए तब तक भूरकी की जान चली गई थी। उन्होंने सायरा थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के गोगुंदा थाना क्षेत्र का होने पर गोगुंदा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपद्धद्य रूपलाल की तलाश जारी है। मृतका के बच्चों के बयान दर्ज किए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव गोगुंदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उत्पीड़न संबंधी एफआइआर के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तारी नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने जस्टिस पीबी वरले और जस्टिस एन आर बोरकर की खंडपीठ को बताया कि अकोला में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। खंबाटा ने कहा कि पुलिस, परमबीर को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक सिंह की याचिका के जवाब में हलफनामा नहीं दायर कर देती। उल्लेखनीय है परमबीर समेत 28 पुलिस वालों के खिलाफ 30 अप्रैल को अकोला में तैनात इंस्पेक्टर भीमराव घडगे ने एफआइआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। खंबाटा ने बताया कि सिंह की याचिका पर हलफनामा देने के लिए पुलिस को थोड़ा समय चाहिए। पुलिस ने राज्य सरकार का वक्तव्य स्वीकार कर लिया। इस मामले पर 20 मई को फिर सुनवाई होगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह घटना 2015 की है लेकिन इसकी एफआइआर 2021 में कराई गई। शिकायतकर्ता को एफआइआर दर्ज कराने में पांच साल लग गए। इस पर परमबीर के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दुर्भावनावश मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि यह एफआइआर पूरी तरह गलत है। ऐसे में याचिकाकर्ता (सिंह) को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इधर, गत दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वह उनपर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। सिंह ने यह बात उच्च न्यायालय में दायर अपनी दूसरी याचिका में भी कही है। यह याचिका सिंह ने राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध शुरू करवाई गई जांच पर रोक लगाने के लिए दायर की है। परमबीर सिंह ने सीबीआइ को लिखे पत्र में कहा है कि 15 अप्रैल को संजय पांडे द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद वह 19 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे। वहां संजय पांडे ने उन्हें सलाह दी कि सिस्टम से लड़ने के कोई फायदा नहीं होगा। आप गृहमंत्री के विरुद्ध लगाए गए अपने सभी आरोप वापस ले लीजिए, तो आपके विरुद्ध चल रही जांच रोक दी जाएगी।

पुलिस थाने में मौत के बाद ग्रामीणों ने जीप जलाई, तोड़फोड़

जयपुर। राजस्थान में टोंक जिले के दत्तावास पुलिस थाने में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद उग्र ग्रामीणों ने बवाल मचा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की जीप आग के हवाले करने के साथ ही थाने में तोड़फोड़ की। कुछ पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की गई। ग्रामीणों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ और आगजनी बुधवार आधी रात बाद की। ग्रामीणों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश ने

बताया कि जगसरा गांव निवासी भवानी मीणा ने बुधवार रात रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई पप्पू बाइक से गांव के बाहर जा रहा था। इस दौरान शराब के ठेकेदार भरत सिंह, घनश्याम, कालू और जगदीश उसे पकड़कर अपने साथ ले गए।

उन्होंने पप्पू के साथ मारपीट की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पप्पू खुद भी अवैध शराब का काम करता था। शराब ठेकेदार ने उसे अवैध शराब के साथ पकड़ा था। उन्होंने पप्पू को दत्तावास पुलिस थाने में सौंप दिया और अवैध शराब का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। इसी बीच, पप्पू को थाने में जोरजोर से खांसी होने लगी। उसे खून की उल्टी हुई और अचानक मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मृतक के भाई ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पप्पू की मौत की खबर फैलते ही बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीण पुलिस थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां खड़ी जीप में आग लगा दी। समझाने का प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ भी ग्रामीणों ने धक्का-मुक्की की। इस पर हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

अब तक ग्रामीणों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। शव स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। ग्रामीण थाने में पप्पू की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं।

कोरोना महामारी के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते का खतरा, अधिकारियों को चौकस रहने के आदेश

अहमदाबाद । कोरोना महामारी के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते का खतरा, अधिकारियों को चौकस रहने के आदेश कोरोना महामारी के बीच गुजरात पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चक्रवाती तूफान से फसलों को नुकसान हो सकता है। अरब सागर में आगामी 14 मई यानी शुक्रवार को लो प्रेशर बनने की संभावना है, जो शनिवार को डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है तथा 16 मई को गुजरात के पूर्व मध्य अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठने की संभावना है। चक्रवात सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात के समुद्री किनारे से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात के समुद्री तट पर 16 से 18 मई तक चक्रवात तौकते का खतरा रहेगा। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने चक्रवात बनने तथा उससे होने वाले नुकसान की संभावनाओं पर सरकार के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की।

उन्होंने सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात के साथ अन्य जिलों के कलेक्टर जिला विकास अधिकारी तहसीलदार तथा राजस्व अधिकारियों को चौकस रहने को कहा गया है। जडेजा ने समीक्षा बैठक के बाद सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात के जिला कलेक्टर को खास हिदायत देते हुए बताया कि समुद्र में गए मछुआरों को सुरक्षित बुला लिया जाए तथा तटरक्षक बल की मदद से चक्रवात व तूफान से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियां की जाए। बताया जा रहा है कि अब तक करीब एक सौ बोट समुद्र से समुद्री किनारे पर आकर लंगर डाल चुकी है। चक्रवात से सौराष्ट्र के जामनगर भावनगर पोरबंदर तथा दक्षिण गुजरात के सूरत तापी व वलसाड जिले को अधिक खतरा है, इसलिए इन जिलों के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन पुलिस तथा तटरक्षक बल के जवान सतर्क हो गए हैं तथा राहत व बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं।

सरकार ने राजस्व अधिकारियों व अनाज मंडियों के संचालकों को निर्देश जारी कर खुले में रखे

अनाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा है। सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात में आम तथा विविध फल व फूल की फसलों को बचाने के लिए किसान कई उपाय कर रहे हैं। गिर सोमनाथ जूनागढ़ जिलों में किसान आम की कच्ची फसल को ही तोड़ रहे हैं, ताकि बरसात से खराब ना हो। किसानों का मानना है कि अगर चक्रवात के बाद तेज बरसात और तूफान आता है तो 80 फीसद फसलें उसे नष्ट हो सकती हैं।

गुजरात में कोरोना के 10742 नए मामले और 109 लोगों की मौत

अहमदाबाद । गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10742 केस सामने आए, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2878 है, जबकि मौत का आंकड़ा 15 है। प्रदेश में कोरोना से मामूली राहत मिली है। पिछले चौबीस घंटे में राज?य में 15 हजार 269 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। राज्य में हाल सक्रिय केसों की संख्या एक लाख 22847 है।

जबकि अब तक कुल सात लाख 25353 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से पांच लाख 93666 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक राज्य में 8840 की मौत हो चुकी है। गुजरात में गुरुवार को एक लाख 51 हजार 772 का टीकाकरण हुआ, जबकि अब तक एक करोड़ 47 लाख 18861 टीके लगाए जा चुके हैं।

अहमदाबाद महानगर पालिका इलाके में 2878 केस जब 15 की मौत दर्ज की गई, जबकि सूरत महानगर पालिका क्षेत्र में 776 केस व आठ की मौत, वडोदरा महानगर पालिका में 650 केस व छह की मौत, राजकोट महानगर पालिका में 359 केस व चार मौतें, जामनगर महानगर पालिका क्षेत्र में 298 केस व पांच की मौत, भावनगर महानगर पालिका में 202 केस व चार की मौत, जूनागढ़ महानगर पालिका क्षेत्र में 323 केस चार की मौत तथा गांधीनगर महानगर पालिका में कोरोना संक्रमण के 104 मामले सामने आए तथा एक की मौत दर्ज की गई।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

मुंबई । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धनोरा तालुका के मोर्चुल गांव के पास जंगली इलाके में गुरुवार सुबह छह बजे मुठभेड़ हुई। सी-60 के कमांडो के साथ गढ़चिरौली पुलिस की विशेष इकाई की एक टीम और अन्य सुरक्षाकर्मी इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोर्चुल के जंगलों में 25 से ज्यादा नक्सली जमा हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि पुलिस टीम को देखते ही नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद नक्सली घने जंगल की ओर भाग निकले।बाद में इलाके की तलाशी के दौरान पुलिस को दो नक्सलियों के शव मिले। इनमें एक महिला नक्सली का शव है। इलाके से नक्सल संबंधित सामग्री भी मिली है। पुलिस ने कहा कि अभी तक मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है।

गौरतलब है कि अप्रैल, 2018 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। जिसमें पुलिस ने 14 नक्सलियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पुलिस की इस कार्रवाई में नक्सली नेता साईनाथ और सिनू भी मारे गए। गढ़चिरौली जिले के इटापल्ली के बोरीया वन क्षेत्र में महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए। माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ यह इस साल अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले मार्च में छत्तीसगढ़ में 10 नक्सली मारे गए थे। इनमें छह महिला कमांडर थीं।

गढ़चिरौली में सुरक्षाबलों के जवान के अलावा स्थानीय लोग भी नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस राज्य के इस नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस इलाके में ग्रामीणों और नक्सलियों के बीच अक्सर संघर्ष की खबरें आती हैं, इसलिए इलाके से नक्सलियों की सफाई के लिए पुलिस की तरफ से यह अभियान चलाया गया था।

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 21 मई को होगी सुनवाई

जोधपुर । जोधपुर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमित होने के बाद जोधपुर स्थित एम्स में इलाज करा रहे आसाराम की अंतरिम याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एम्स की ओर से आसाराम के स्वास्थ को लेकर रिपोर्ट पेश की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एम्स में ही आसाराम का इलाज करने के आदेश दिए हैं। आसाराम ने आयुर्वेद पद्दति से इलाज करवाने के संबंध में दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन एम्स की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद अब फिर आसाराम की जमानत की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। हाईकोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है। तब तक आसाराम को एम्स में ही रखा जाएगा।

कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम की ओर से अपनी अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी। आसाराम की तरफ से इलाज कराने के लिए दो माह की अंतरिम जमानत देने की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। एम्स की तरफ से बताया गया कि कोरोना संक्रमित आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ में याचिका पर

सुनवाई हुई। ऑनलाइन हुई इस सुनवाई में आसाराम की तरफ से तर्क दिया कि आसाराम को हार्ट में तकलीफ है, साथ ही वे कई बीमारियों से परेशान है। ऐसे में वे आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज कराना चाहते है। इस कारण मानवीय आधार पर जमानत दी जाए।

राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। सरकारी वकील अनिल जोशी ने कहा कि एम्स की तरफ से पेश आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई है। फिलहाल, उसका सिर्फ कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन तक आइसोलेट रहना अनिवार्य है। ऐसे में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई तिथि 21 मई तय कर दी। तब तक आसाराम के कोरोना संक्रमित होने के बाद के 14 दिन भी पूरे हो जाएंगे। साथ ही, एम्स से उस दिन आसाराम के स्वास्थ्य की ताजा रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके बाद ही आसाराम की इलाज के संबंध में लगाई गई जमानत याचिका पर फैसला हो पाएगा।

बंगाल के राज्यपाल की हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा असंवैधानिक, तृणमूल ने की कड़ी आलोचना

कोलकाता । बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा से प्रभावित कुचबिहार जिले के विभिन्न स्थानों का गुरुवार को दौरा करने के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार व मुख्यमंत्री की सलाह की अनदेखी करते हुए कूचबिहार में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को धनखड़ को पत्र लिखकर दावा किया था कि कूचबिहार जाने का उनका फैसला कई दशकों से चली आ रही लंबी परंपरा व मानदंडों का उल्लंघन है और उन्होंने राज्यपाल से इस दौरे पर जाने से परहेज करने का आग्रह किया था। इसके बाद राज्यपाल ने अपने जवाब में कहा कि वह संविधान द्वारा अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और कूचबिहार की उनकी यात्रा चुनाव के बाद की हिंसा से पीड़ित लोगों के दर्द और पीड़ा को साझा करने के लिए है। वहीं, तृणमूल के वरिष्ठ सांसद और प्रवक्ता सौगत राय ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, उन्होंने (धनखड़) राज्य सरकार की बात नहीं मानी और कूचबिहार चले गए।

वह भाजपा नेता के साथ गए थे। उनका आचरण असंवैधानिक है। दरअसल, कूचबिहार से भाजपा सांसद निशिथ प्रमाणिक भी धनखड़ के साथ जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों की यात्रा के दौरान थे। तृणमूल सांसद ने कहा, पहले हमने इस राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। यदि सीएम कहती हैं, तो हम उनके खिलाफ एक और पत्र राष्ट्रपति को भेजेंगे।

तृणमूल के कई सांसदों ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बंगाल के राज्यपाल के पद से जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से राज्य प्रशासन के खिलाफ नियमित रूप से टिप्पणी करके संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इधर, पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भी दावा किया कि धनखड़ का आचरण राज्यपाल के प्रति असंतुलित है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल चुनाव के बाद की कुछ घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वह तब राजनीति कर रहे हैं जब राज्य महामारी से लड़ने में व्यस्त है। हम चाहते हैं कि राज्यपाल और राज्य सरकार कोविड से लड़ने के लिए मिलकर काम करें।इसके अलावा तृणमूल की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी ट्विटर के माध्यम से राज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि यह समय राजनीति करने की नहीं है।

राजस्थान में कोरोना के 15867 नए मामले और 159 की मौत

जयपुर । राजस्थान में वीरवार को कोरोना के 15,867 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही 159 पीड़ितों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक आठ लाख 21 हजार 525 संक्रमित मिले हैं। मृतकों की कुल संख्या 6317 है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या दो लाख 11 889 है। पिछले 24 घंटे में 12,929 पीड़ित स्वस्थ हुए हैं। इसी बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी से अब तक 11 राज्य वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। इससे राज्यों को अलग-अलग कीमत की वैक्सीन मिलेगी। अच्छा तो यह होता कि भारत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती एवं राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाती, क्योंकि संपूर्ण वैक्सीनेशन से ही कोरोना की

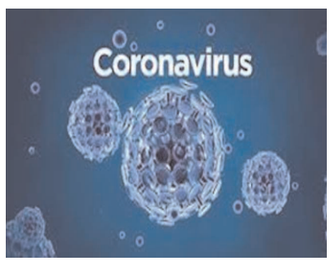

तीसरी लहर से बचा जा सकता है।

प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी हुई है। प्रतिदिन करीब दो लाख डोज लगाई जा रही है। वर्तमान में करीब तीन लाख डोज ही शेष बची है। शुक्रवार तक यदि वैक्सीन विभिन्न एजेंसियों से यहां नहीं पहुंचती है तो शनिवार को टीकाकरण का काम रोका जा सकता है। टीकाकरण के निदेशक डॉ.रघुराज सिंह ने बताया कि अब हमारी पहली प्राथमिकता दूसरी डोज की वेटिंग में खड़े लोगों को टीका लगाने की है। उधर, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन एवं नियमों की पालना के लिए राजस्थान एपेडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 20 लाख 48 हजार से अधिक लोगों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर चार लाख 52 हजार 208, बिना मास्क पहले लोगों को सामान बेचने पर 20,505, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी का पालन नहीं करने पर 15 लाख 23 हजार 691 लोगों के चालान किए गए हैं। बिना वजह सड़कों पर घूमने के कारण अब तक 20 लाख 93 हजार 947 वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही दो लाख 44 हजार 875 वाहन जब्त किए गए। वाहनों से अब तक 40.72 करोड़ का जुर्माना वसूला जा चुका है।

अर्जुन कपूर को इंडस्ट्री में नौ साल पूरे, मां को याद करते हुए लिखा भावुक पोस्ट

अर्जुन कपूर अपनी मां मोना शौरी कपूर के बेहद करीब थे। अपने इंस्टाग्राम पर अर्जुन असर मां से जुड़ी यादें साझा करते रहते हैं। मदर्स डे के एक दिन बाद अभिनेता ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उनके बॉलीवुड में डेब्यू से पहले ही मोना कपूर का निधन हो गया था। अर्जुन कपूर ने अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें वो अपनी मां के साथ हैं। तस्वीर में अर्जुन का वजन काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'कल मदर्स डे था। मैं इससे हर तरह से नफरत करता हूं। मुझे अभिनेता के रूप में नौ साल हो चुके हैं लेकिन मैं अभी भी मां आपके बिना खोया हुआ सा हूं। बस इस तस्वीर के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे देखने के साथ मुस्कुरा रही हैं और मेरी पीठ सहला रही हैं।'

नौ साल पहले किया था डेब्यू

बता दें कि अर्जुन कपूर ने फिल्म 'इशकजादे' से डेब्यू किया था। फिल्म 11 मई 2012 को रिलीज हुई थी और बॉस ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसमें उनके साथ परिणीति चोपड़ा की मुख्य भूमिका थी। वहीं मोना कपूर का निधन मार्च 2012 में हुआ था।

मां की याद में कही थी ये बात

टीवी शो 'स्टार वर्सेस फूड' के एक एपिसोड के दौरान अर्जुन कपूर ने कहा- 'जब मेरे माता-पिता अलग हुए थे, मैं खाने में सुकून ढूंढने लगा था। मैं इससे एक तरीके से भावुक रूप से जुड़ गया था, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया था, और तब मैं खाने को खूब एंजॉय करने लगा'। उन्होंने बताया कि 'एक प्वॉइंट के बाद जब आपको कोई रोकने वाला नहीं हो तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपकी मां आपसे प्यार करती हैं लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चा है और यही खाने की उम्र है'।

जिंदगियों को बचाने के लिए हम भारतीयों ने जिस तरह हाथ मिलाया है, उस पर मुझे गर्व

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर देश भर के कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की मदद के लिए जी-जान से जुटी हैं। उन्होंने कोविड वॉरियर नाम से एक सोशल मीडिया पहल की शुरुआत की है, जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से साथी नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय एकजुट हुए हैं उसको लेकर भूमि गर्व महसूस करती हैं। भूमि कहती हैं, महामारी ने हमें उन तरीकों और रूपों में एकजुट किया है जैसे हम पहले कभी नहीं थे। संकट और दुःख की घड़ी में हम एकजुट हो गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एकजुट हुए हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, हम जिंदगियां बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, हम मानवता की खातिर एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं हर उस भारतीय को धन्यवाद देना चाहती हूं जो साथी नागरिकों को बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए आगे आए हैं। जिंदगियों को बचाने के लिए जिस तरह हम भारतीयों ने हाथ मिलाया है, एक नागरिक के तौर पर मुझे उस पर गर्व है। भूमि लोगों को बचाने के लिए अथक रूप से कोशिश कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। उनकी इस पहल से कई लोगों की जान बचाने में सफलता मिली है। वे कहती हैं, कोविड वॉरियर ने अच्छाई के लिए सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया है। इसने साझा दुश्मन से लड़ रहे लोगों को एकजुट करने के लिए डिजिटल की ताकत का उपयोग किया है। संकट की घड़ी में लोगों ने जिस तरह से एक-दूसरे के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है, उससे मैं हैरत में हूँ। मुझे पता है कि इस वायरस पर काबू पाने तक हमें लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं अपने हर पल का इस्तेमाल इससे लड़ने और किसी को बचाने के लिए कर रही हूं। भूमि कहती हैं, मैं जानती हूं कि इस डिजिटल फ्रंटियर पर हर भारतीय मेरे साथ खड़ा है और जरूरतमंद लोगों की मदद पहुंचाने के लिए अपना हर पल व्यतीत कर रहा है। हम इस संकट के दौर से निकलेंगे। हम इस वायरस पर जीत हासिल करेंगे, फिलहाल हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं।

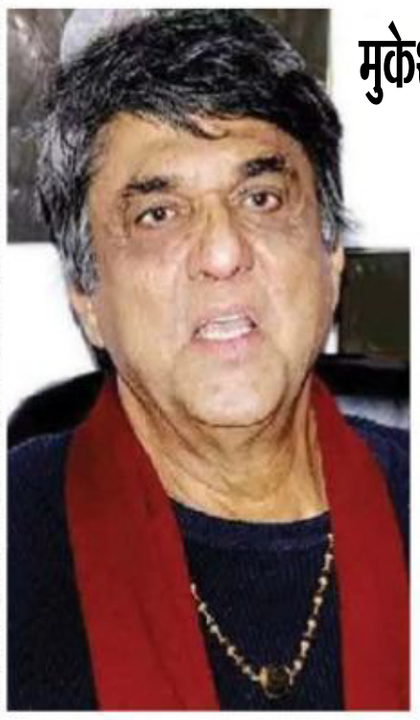

मुकेश खन्ना ने मौत की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा- मैं बिल्कुल ठीक हूं

अनुभवी अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपनी मौत संबंधी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दरअसल, ऐसी अफवाह फैल गई थी कि खन्ना का निधन हो गया है। इसके बाद अभिनेता (62) ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इन अफवाहों का खंडन किया। खन्ना ने फेसबुक पर छोटी-सी वीडियो पोस्ट करके कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। अभिनेता ने कहा, ''मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं अफवाहों का खंडन करता हूं, मुझे इनका खंडन करने के लिए कहा गया था और मैं भी यह करना चाहता हूं।'' 'शक्तिमान' में सुपरहीरो और टेलीविजन धारावाहिक ''महाभारत'' में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने के लिए पहचाने जाने वाले खन्ना ने झूठी खबरों को लेकर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा, ''मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। सोशल मीडिया की यही दिक्कत है। मानसिक रूप से अस्थिर ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? उनके कुकृत्यों की सजा कौन देगा? बस बहुत हुआ। अब यह बहुत ज्यादा है। ऐसी फर्जी खबरों पर रोक लगनी चाहिए।'' वीडियो के शीर्षक में खन्ना ने कहा कि वह कोविड-19 से संक्रमित नहीं हैं। उन्होंने लिखा, ''आपकी दुआओं के कारण मैं पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हूं। मुझे कोविड-19 नहीं है और मुझे किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया।'' खन्ना ने कहा, ''मुझे नहीं पता किसने यह अफवाह फैलायी और मैं नहीं जानता कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले की मंशा क्या है। वे ऐसी झूठी खबरें फैलाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं।

फिल्म सालार में डबल रोल निभा सकते हैं प्रभास

साउथ सुपरस्टार प्रभास जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इनमें से एक फिल्म 'सालार' भी है। यह फिल्म अगले साल 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आने वाले हैं। खबर है कि 'सालार' में प्रभास डबल रोल करते दिखेंगे। इससे पहले उन्हें 'बाहुबली' में दोहरी भूमिका में देखा गया था और अब 'सालार' से दर्शकों को दोबारा मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है। प्रभास ने पिछले साल इस फिल्म की घोषणा करते हुए कहा था, मैं हमेशा से प्रशांत नील के निर्देशन में एक अभिनेता बनकर काम करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि एक अभिनेता के रूप में मुझे उनके साथ काम करने का इससे बढ़िया मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, यह एक बहुत शानदार फिल्म है और इसमें मेरा किरदार बेहद हिंसक है। यह कुछ ऐसा है, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। मेरा खूंखार रूप देख दर्शक हैरान रह जाएंगे। कन्नड़ फिल्म 'सालार' का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' का निर्देशन किया था। इस बिग बजट की फिल्म के निर्माता विजय किरागंदुर हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री श्रुति हासन लीड एक्ट्रेस की भूमिका में हैं। फिल्म में अभिनेत्री राम्या कृष्णन 'सालार' में प्रभास की बड़ी बहन की भूमिका निभा सकती हैं। इस फिल्म को हिन्दी, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब किया जाएगा। प्रभास जल्द ही फिल्म 'राधे श्याम' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी। इस फिल्म में प्रभास लंबे समय बाद किसी रोमांटिक रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा प्रभास फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं। प्रभास निर्देशक नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म और 'रैम्बो' के हिन्दी रीमेक में नजर आएंगे। वह सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में भी कैटरीना कैफ के साथ नजर आ सकते हैं।

सलमान खान की 'राधे' का बनेगा सीक्वल, लेकिन यह है शर्त

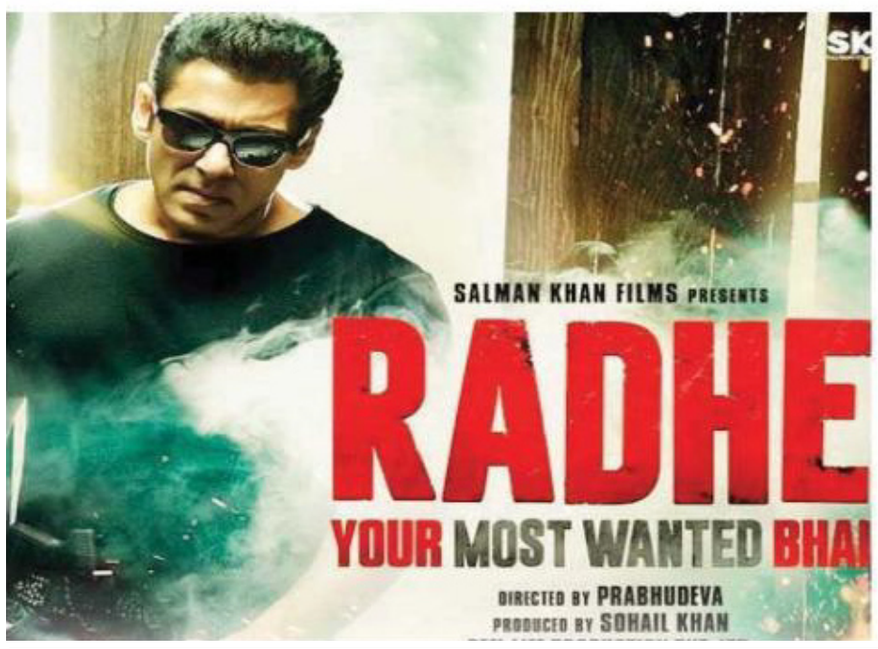

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म 'राधेः योर मोस्ट वांटेड भाई' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। यह फिल्मी ईद के साथ मौके पर यानी 13 मई को रिलीज होने जा रही है। सलमान इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सलमान खान के 'राधे' को लेकर कई सवाल पूछे गए। ऐसे में अभिनेता से फिल्म के सीक्वल और 'राधे' की 'वांटेड' से तुलना को लेकर भी सवाल किए गए।

सलमान का कहना है कि उनकी इस फिल्म का सीक्वल भी आ सकता है। अफवाहें थीं कि 'राधे' फिल्म 'वॉन्टेड' का सीक्वल है। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि दोनों फिल्मों के निर्देशक प्रभुदेवा हैं। दोनों ही फिल्मों में सलमान पुलिसवाले बने हैं और दोनों ही फिल्मों में 'कमिटमेंट' वाला डायलॉग है।

इस पर सलमान ने कहा, दोनों फिल्मों में कोई समानता नहीं है। सिर्फ कमिटमेंट वाला डायलॉग वही है। वॉन्टेड का सीक्वल कभी नहीं आएगा, लेकिन 'राधे' को यदि दर्शकों से अच्छा रिस्पॉस मिला तो इसका सीक्वल जरूर बनाएंगे।

सलमान ने कहा, 'हमारी फिल्म 'राधे' मल्टीप्लेक्स या सिंगल थियेटर में रिलीज होने जैसी फिल्म है। हमने फिल्म बनाई ही ऐसी है। सबकी तरह हमें भी यही लग रहा था कि सबकुछ सामान्य हो जाएगा।

उन्होंने कहा, जैसे ही हमने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया, वैसे ही फिर से ये कोरोना बाबा शुरू हो गए। खैर, हमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इस मुश्किल घड़ी में हम अपने प्रशंसकों का दिल जरूर बहलाएंगे। राधे ऐसे समय में रिलीज हो रही है, जब अधिकतर लोग घरों में ही रहना चाहते हैं और यही उनके लिए सही भी है। समय बेहतर हुआ तो ये फिल्म सिनेमाघरों में नए सिरे से भी रिलीज हो सकती है।

उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग अभी सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाएं। फिर कोरोना होने पर मेरी फिल्म को दोष दें और कहें सलमान की पिक्चर देखने गए और कोरोना फैल गया।

प्रभु देवा के निर्देशन में बनी 'राधे' में सलमान के साथ दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी प्रमुख भूमिका में हैं। दिशा इसमें जैकी की बहन का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज एक आइटम नंबर पर थिरकती नजर आएंगी।

इस फिल्म को सोहेल खान, सलमान खान और अतुल अग्निहोत्री ने मिलकर बनाया है। यह सलमान के करियर की सबसे छोटी फिल्मों में से एक है, जो दो घंटे से कम अवधि की है। सलमान फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। इसमें वह अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते दिखेंगे।

फोर्ब्स की लिस्ट: मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार मैक्ग्रिगोर ने कमाई में मेसी, रोनाल्डो और फेडरर को पीछे छोड़ा

पिछले साल से 971 करोड़ रुपये ज्यादा कमाए

नई दिल्ली। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप-10 एथलीट की लिस्ट जारी की। इसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैक्ग्रिगोर टॉप पर हैं। उन्होंने कमाई के मामले में फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया। मैक्ग्रिगोर ने पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 971 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। लिस्ट के मुताबिक, मैक्ग्रिगोर की सालाना कमाई करीब 1,324 करोड़ रुपए रही। इसमें उन्होंने करीब 1,163 करोड़ रुपए एंडोर्समेंट यानी विज्ञापन और बाकी चीजों से कमाए। जबकि, 161 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स से कमाए। मैक्ग्रिगोर की पिछले साल की कमाई करीब 353 करोड़ रुपए थी और वे फोर्ब्स की लिस्ट में 16वें नंबर पर थे।

अर्जेंटीना और स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी सालाना कमाई करीब 956 करोड़ रुपए रही। 2020 में वे करीब 765 करोड़ रु. की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर थे। वहीं, पिछले साल दूसरे नंबर पर मौजूद रोनाल्डो इस बार लिस्ट में तीसरे नंबर पर लुढ़क गए। उनकी सालाना कमाई करीब 883 करोड़ रुपए रही। यह पिछले साल करीब 772 करोड़ रुपए थी। अमेरिकन फुटबॉलर डेक प्रेस्कॉट करीब 791 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ चौथे और दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स करीब 710 करोड़ की कमाई के साथ पांचवें नंबर पर रहे। लेब्रॉन को पिछले साल TIME मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया था।

हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया?

इसमें 1 मई, 2020 से लेकर 1 मई, 2021 तक किसी एक एथलीट द्वारा की गई कमाई को शामिल किया गया है। इसमें प्राइज मनी, सैलरी और बोनस शामिल है। एंडोर्समेंट इनकम में 1 साल के दौरान स्पॉन्सरशिप्स, अपियरेंस फी और लाइसेन्सिंग से मिली रकम को जोड़ा जाता है। इसके लिए इंडस्ट्री के अंदर के लोगों से जानकारी ली जाती है। इसमें टैक्स, एजेंट फी और इन्वेस्टमेंट इनकम को नहीं जोड़ा जाता है।

मैनचेस्टर सिटी ने जीता प्रीमियर लीग खिताब

लंदन। मैनचेस्टर सिटी ने 2020/21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लिसेस्टर सिटी के मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराते ही सिटी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। पिछले 4 सीजन में सिटी का यह तीसरा प्रीमियर लीग खिताब है। पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैम्पियन बन चुकी है। इसमें से 2 बार टीम गार्डियोला की कोचिंग में चैम्पियन बनी है। अब मैनचेस्टर सिटी को 30 मई को चेल्सी के खिलाफ UEFA चैम्पियंस लीग का फाइनल खेलना है।

सिटी ने पांचों प्रीमियर लीग खिताब पिछले 10 साल में जीते हैं। यह EPL के किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा है। इसके बाद चेल्सी ने 2 और लिसेस्टर सिटी, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1-1 बार यह खिताब अपने नाम किया। सिटी के 35 मैच में 80 पॉइंट्स हैं। वहीं, यूनाइटेड के इतने ही मैच में 70 पॉइंट्स हैं। दोनों के पास अब 3-3 मैच बचे हैं। ऐसे में यूनाइटेड का 10 पॉइंट की लीड ले रहे सिटी से पार पाना नामुमकिन है। यह 2016 में गार्डियोला के सिटी के कोच बनने के बाद से 10वीं ट्रॉफी है। सिटी ने इससे पहले 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 में भी प्रीमियर लीग खिताब जीता था। यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा 13 बार EPL खिताब अपने नाम किया है, वहीं सिटी के अलावा चेल्सी ने भी बार ये ट्रॉफी जीती है।

टिम पेन ने कर दी घोषणा कब छोड़ देंगे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम की कप्तानी, कहा- स्मिथ बने अगले कप्तान

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि, अगर उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ष इंग्लैंड के खिलाफ एशेज जीत लेती है तो वो कप्तानी को अलविदा कर देंगे। इसके बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को अगला टेस्ट कप्तान बनाए जाने की भी बात कही। इस सीजन की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी धरती पर टेस्ट सीरीज में हरा दिया था और इसके बाद से उनकी कप्तानी को लेकर काफी बातें हो रही है साथ ही उन पर कप्तानी से हटने का भी दवाब है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ साल 2018 में गेंद से छेड़छाड़ वाली घटना से पहले कंगारू टेस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं।

टिम पेन ने कहा कि, मैंने स्टीव स्मिथ की कप्तानी में जितना भी खेला है वो शानदार था साथ ही उनकी तकनीक बेहतरीन है। उन्हें काफी कम उम्र में ही कप्तानी सौंप दी गई थी और वो उसके लिए तैयार नहीं थे। वो काफी कुछ मेरी तरह ही हैं। हालांकि जब तक मैं टीम में आया वो परिपक्व हो चुके थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका में वो घटना हो गई। वैसे मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि, उन्हें अगला टेस्ट कप्तान बनाया जाए। पेन ने संकेत दिए कि, अगर इस साल उनकी टीम एशेज जीत जाती है तो वो कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि, कम से कम अगले छह टेस्ट तक तो मैं कप्तान हूं । मुझे लगेगा कि समय सही है और हम एशेज में आस्ट्रेलिया का सफाया कर देते हैं तो वह जाने का सही समय होगा। भारत के खिलाफ सीरीजके बारे में उन्होंने कहा कि वे आपका ध्यान हटाने में माहिर हैं। हम उसी में फंस गए।

आईपीएल में खेलता नजर आ सकता है ये पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज, चल रही तैयारी

नई दिल्ली। बीसीसीआई की इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टी20 लीग में से एक है। इसमें खेलने का सपना दुनियाभर के क्रिकेटर देखते हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग आइपीएल की नीलामी में शामिल होने के लिए अपना नाम भेजते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में खेलने पर पाबंदी है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से बीसीसीआइ ने यह फैसला किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर आइपीएल में खेलते नजर आ सकते हैं। विवादों की वजह से महज पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आमिर ने ब्रिटिश नागरिकता के लिए अर्जी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने के बाद अब वह विदेशी लीग में खेल रहे हैं। अगर उनको ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो वह आइपीएल में खेल सकते हैं। आमिर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मुझे इस वक्त अनिश्चित समय के लिए यूनाइटेड किंगडम में रहने की इजाजत मिल चुकी है। मैं इन दिनों अपनी क्रिकेट को और ज्यादा मजे से खेल रहा हूं और अगले 6-7 साल तक खेलने का इरादा है। मेरे बच्चे इंग्लैंड में बड़े हो रहे हैं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर तो कोई शक ही नहीं कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त यहीं बिताउंगा। मैं कई अलग चुनौती और संभावनाओं की तलाश में हूं देखना होगा आगे जब मुझे ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो चीजों कैसे होती है।

क्या श्रीलंका में जीतेगी भारत की बी टीम:युवाओं के कंधों पर जब भी आया दारोमदार, टीम चैम्पियन बनकर लौटी

नई दिल्ली। टीम इंडिया जून में इंग्लैंड दौरे पर जा रही है। वहां, 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के बाद अगस्त-सितंबर से मेजबान टीम के साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। इस बीच BCCI ने बताया है कि जुलाई में भारत की एक अन्य टीम श्रीलंका के दौरे प्र जाएगी। इसमें इंग्लैंड दौरे पर गया कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं होगा। कहा जा सकता है कि श्रीलंका दौरे पर भारत की बी टीम जाएगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि युवा खिलाड़ियों से बनी यह टीम क्या श्रीलंका को उसके घर में हरा पाएगी? इस सवाल का जवाब हम इतिहास से पूछने की कोशिश करते हैं। यानी पहले के ऐसे वाकये जब कई सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, तब टीम नेकैसा खेल दिखाया?

2007 टी-20 वर्ल्ड कप है सबसे बड़ी मिसाल

सीनियर खिलाड़ियों के न होने पर भारतीय टीम कैसा खेल दिखाती है इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2007 में हुआ पहला टी-20 वर्ल्ड कप है। तब टीम के तीन सीनियर खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने खुद को टूर्नामेंट से अलग कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में युवा टीम चुनी गई। इसमें रोहित शर्मा, जोगिंदर शर्मा, रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान, आरपी सिंह जैसे कई युवा खिलाड़ी शामिल थे।

सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने खुद को टूर्नामेंट से अलग कर लिया था

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में युवा सितारों से लैस टीम इंडिया चैम्पियन बन कर लौटी

युवराज, हरभजन, इरफान भी ज्यादा पुराने नहीं थे। इस टीम ने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिया और चैम्पियन बनी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट भी हमेशा के लिए बदल गया। देश में अगले साल से टी-20 लीग द्धक्कभी शुरू हो गई।

निदाहास ट्रॉफी में भी टीम बनी चैम्पियन

2018 में धोनी, विराट सहित भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ी श्रीलंका में हुई टी-20 त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेने नहीं गए। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम घोषित हुई। इसमें लोकेश राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, जयदेव उनादकट, दीपक हुडा जैसे कई कम अनुभवी खिलाड़ी भी चुने गए। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण था।

इस टीम ने भी फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। इसी टूर्नामेंट के फाइनल में दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई थी।

2020 ऑस्ट्रेलिया दौरा

2007 वर्ल्ड कप और निदाहास ट्रॉफी टी-20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट था। इसमें अक्सर युवा जोश अच्छा माना जाता है, लेकिन भारतीय युवाओं ने 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 36 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कप्तान विराट कोहली बच्चे के जन्म के कारण भारत लौट आए ेथ फिर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी एक-एक कर चोटिल होते गए।

WTC फाइनल से पहले तैयारी की कमी: भारत के फील्डिंग कोच श्रीधर बोले- तैयारी न होना फायदेमंद भी हो सकता है, खिलाड़ी ज्यादा फोकस होकर खेलेंगे

कराची। टीम इंडिया को 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है। टीम जून के पहले सप्ताह में इंग्लैंड पहुंच जाएगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण खिलाड़ियों को तैयारी का बहुत कम मौका मिलेगा। इस पर भारतीय टीम के फील्डिंग कोच आर. श्रीधर का मानना है कि तैयारी की कमी भारत के पक्ष में भी काम कर सकती है। इससे खिलाड़ी ज्यादा फोकस होकर खेलेंगे।

कम तैयारी के साथ खेलना चोट के साथ खेलने जैसा

श्रीधर ने कहा कि कम तैयारी के साथ खेलने का मतलब होता मानो आप किसी चोट के साथ खेल रहे हैं। जब खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद खेलता है तो उसका फोकस ज्यादा होता है। वह कम से कम गतलियां करने की कोशिश करता है। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर टीम के खिलाड़ियों को तैयारी का मौका कम मिलता है तो इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

मानसिक रूप से स्मार्ट होने की जरूरत

श्रीधर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को इस वक्त मानसिक रूप से स्मार्ट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'टीम के हर खिलाड़ी के पास स्थिति के अनुकूल ढलने की क्षमता है। ज्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल चुके हैं और इंग्लैंड में भी खेल चुके हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि इनका अनुभव काम आएगा। श्रीधर ने कहा, 'हम यह प्लान नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कितने सेशन होंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा क्वारैंटाइन कितना कड़ा होगा। इसलिए अगर हम शारीरिक रूप से बहुत तैयारी भले न कर पाएं, खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।'

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने भी कम तैयारी के मसले पर अपनी राय रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फाइनल के लिए थोड़ा बेहतर तैयार होंगे।

गावस्कर ने की पंत की तारीफ: पूर्व क्रिकेटर ने कहा-

भविष्य में पंत एक शानदार कप्तान बन सकते हैं, उनमें मैच जीतने की भूख है

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने IPL में ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ की है और उन्हें भविष्य में भारतीय टीम का कप्तान बताया है। पंत को IPL के 14वें सीजन में नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह पर कप्तानी सौंपी गई थी। अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे मैच में चोट लग गई थी। जिसकी वजह से वे IPL नहीं खेल सके।

गावस्कर ने स्पोर्ट्स स्टार में लिखे कॉलम में कहा है कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज पंत के अंदर मैच जीतने की ललक नजर आई। पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। छठे मैच तक यह देखा जा सकता था कि वे कप्तानी पर सवाल पूछे जाने से थक चुके थे। हर प्रजेंटर मैच खत्म होने के बाद उनकी कप्तानी को लेकर ही सवाल कर रहे थे। मुझे उनमें मैच जीतने का जज्बा दिखा। उन्हें अगर नेचुरल रूप से आगे बढ़ने दिया जाए तो वे भविष्य में बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं।

कंधे की चोट की वजह से अय्यर नहीं खेल सके: श्रेयस अय्यर पिछले दो सालों से दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं। यूएई में हुए पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहली बार अय्यर की कप्तानी में फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा और टीम उपविजेता रही। अय्यर कंधे में चोट की वजह से IPL 2021 से बाहर हो गए थे। जिसके बाद पंत को टीम की कप्तानी सौंपी गई।

IPL के 14वें सीजन को कोरोना के मामले आने के बाद बीच सेशन में ही रोकना पड़ा। तब तक

60 मैचों में से 29 मैच हो चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों के बाद पॉइंट टेबल में टॉप पर थी। दिल्ली ने 8 मैचों में से 6 मैच जीते थे, जबकि दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार IPL में कप्तानी कर ऋषभ पंत की आईपीएल 14 में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 8 पारियों में 35.50 की औसत से 213 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131.48 था।

सिंगापुर ओपन कैंसिल: साइना 2008 के बाद पहली बार ओलिंपिक में नहीं खेलेंगी

श्रीकांत की भी ओलिंपिक खेलने की उम्मीद खत्म

सिंगापुर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने कोरोना की वजह से सिंगापुर ओपन को रद्द कर दिया है। यह ओलिंपिक क्वालिफाइंग का अंतिम टूर्नामेंट था। इसके साथ ही साइना नेहवाल की टोक्यो ओलिंपिक में खेलने की उम्मीद खत्म हो गई। 2008 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि नेहवाल ओलिंपिक में नहीं खेल पाएंगी। नेहवाल के साथ ही किदांबी श्रीकांत का भी खेल पाने का सपना खत्म हो गया।

सिंगापुर का आयोजन 1 से 6 जून तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से कई देशों के बीच हवाई यात्रा पर बैन लगा हुआ है। इस वजह से बीडब्ल्यूएफ ने टूर्नामेंट को कैंसिल करने का फैसला किया। बीडब्ल्यूएफ ने कहा, 'सभी खिलाड़ियों, टूर्नामेंट कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हितों को देखते हुए टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है।

नेहवाल और श्रीकांत के लिए सिंगापुर ओपन था महत्वपूर्ण

साइना और श्रीकांत के लिए टोक्यो ओलिंपिक में जाने की आखिरी उम्मीद सिंगापुर ओपन पर ही टिकी हुई थी। मलेशिया ओपन 25 से 30 मई के बीच होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में सिंगापुर टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर इन दोनों खिलाड़ियों के ओलिंपिक का रास्ता तय होना था, लेकिन सिंगापुर ओपन के कैंसिल हो जाने से यह उम्मीद भी खत्म हो गई।

लंदन ओलिंपिक में जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज मेडल:भारत के लिए नेहवाल ने 2012 लंदन ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के लिए

ओलिंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी रहीं। भारत को ओलिंपिक के इतिहास में बैडमिंटन में दो मेडल मिले हैं। साइना के अलावा 2016 रियो ओलिंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था।

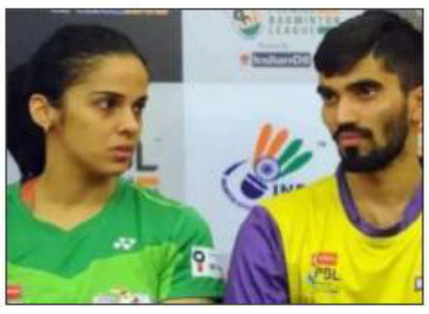

मलेशिया और सिंगापुर ओपन स्थगित होने से साइना और श्रीकांत को झटका लगा है। रैंकिंग में बदलाव नहीं होता है तो सिर्फ सिंधु, प्रणीत को सिंगल्स में और और रंकीरेड्डी-चिराग की जोड़ी को डबल्स में ओलिंपिक कोटा मिलेगा।

एशेज सीरीज 9 दिसंबर से : 26 साल में पहली बार फाइनल मुकाबला सिडनी की जगह पर्थ में होगा; ब्रिस्बेन से सीरीज की शुरुआत होगी

मेलबर्न। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज का आखिरी मैच 26 साल में पहली बार सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगी। द ऐज के मुताबिक 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 16 जनवरी से पर्थ में होगा। 1995 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सीरीज का आखिरी मैच सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ के अलावा सीरीज के चार मैच ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे।

गाबा से सीरीज की शुरुआत

ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत ब्रिस्बेन के गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम से करेगी। इस स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया को इस साल भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में 32 साल बाद हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की थी।

ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले 1988 में वेस्टइंडीज ने 9 विकेट से शिकस्त दी थी।

वहीं 2003 में भारत ने बराबरी पर रोका था। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अब तक 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 33

जीते हैं। जबकि 13 ड्रॉ रहे हैं और केवल नौ में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, एक मैच टाई रहा है।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज का आखिरी मैच 26 साल में पहली बार सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगी।

एशेज से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा वॉर्मअप मैच

इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान के साथ अक्टूबर-नवंबर में एक टेस्ट मैच खेलेगी। अफगानिस्तान को टेस्ट का दर्जा मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार उसके खिलाफ खेलेगी।

अफगानिस्तान को 2018 में टेस्ट का दर्जा मिला है। अब तक अफगानिस्तान ने केवल 6 टेस्ट मैच भारत, आयरलैंड, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेले हैं।

एडिलेड में दूसर टेस्ट मैच डे नाइट: सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में डे नाइट होगा। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है। लेकिन द ऐज के मुताबिक एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच 16 नवंबर से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में आठ डे नाइट मैच खेले हैं और सभी मैच जीते हैं।

तीसरा और चौथा मैच मेलबर्न और सिडनी मेंहालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज की शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा मैच बॉक्सिंड डे पर मेलबर्न में शुरू होगा और नए साल में सिडनी में चौथा मैच खेला जाएगा।